● वर्ष-3
● अंक-259
रायपुर, शनिवार
08 जून 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› शादी के 1 महीने पहले कर लें ये काम...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया

मोदी और 5 बरस, 9 जून को शपथ

नई दिल्ली। तमाम अटकलों के बीच एनडीए की बैठक ने बहुत कुछ साफ कर दिया। नरेंद्र मोदी एनडीए दल के नेता चुन लिए गए और अपनी स्पीच से साफ भी कर दिया कि न वो किसी अंडर प्रेशर् में हैं और न ही किसी दबाव में हैं। मोदी ने साफ कहा की तीसरा टर्म बड़े फैसले वाला होगा। जो लोग एनडीए की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, दरअसल वो अपनी हार और हताशा को छिपाने की कोशिश कर रहे है। जबकि सच्चाई ये है कि न वो हारे थे, हारे हैं और हारेंगे। 9 जून को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। उससे पहले आज एनडीए की एकजुटता और मजबूती को हर किसी ने देखा। जो लोग एनडीए में फूट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सारी तस्वीरों ने उस नैरेटिव को तोड़ दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्पति भवन में राष्ट्पति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद राष्ट्पति ने एनडीए के नेता पीएम मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नरेंद्र मोदी रविवार (9 जून) शाम 6 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्पति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार को जनता ने तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। मैं देश के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पिछले दो कार्यकाल में देश जिस तेजी से आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में बदलाव दिख रहा है और 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना हर भारतवासी के लिए गर्व का क्षण है।

एनडीए ने पीएम मोदी को अपना नेता चुना- इससे पहले दिन में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया, जिससे उनके तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। संसद भवन में नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक भी हुई। संसद भवन के संविधान सदन में हुई बैठक में प्रधानमंत्री का स्वागत मोदी-मोदी के नारों से किया गया. जैसे ही वह बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, प्रधानमंत्री ने सम्मानपूर्वक भारत के संविधान को अपने माथे से लगाया।

लोकसभा चुनाव 2024- आपको बता दें कि बीजेपी ने 240 सीटें जीतीं और कांग्रेस 99 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. एनडीए के पास 293 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा है और सरकार गठन पर समानांतर बैठक चल रही है. वहीं, विपक्षी गठबंधन के पास 234 सीटें हैं. हालांकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई, लेकिन हालात के मुताबिक वह अपने सहयोगियों के दम पर सरकार बना सकती है। आंध्र प्रदेश और बिहार में क्रमशः 16 और 12 सीटें जीतने वाली नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडी (यू) और अन्य गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से, एनडीए ने आधे का आंकड़ा पार कर लिया है।

5 साल रहने का नीतीश ने दिलाया विश्वास

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (यूनाइटेड) ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचकर जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश की बहुत सेवा की है और बाकी बचे हुए लक्ष्य आगामी 5 साल में पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार हारी हुई सीटों पर भी एनडीए अगले चुनाव में निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने आज तक देश की सेवा नहीं की है। वे सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम करते हैं। जिसकी वजह से विपक्ष के लिए आगामी चुनाव में जीत दर्ज करने की लगभग सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। नीतीश कुमार ने विश्वास दिलाया कि उनकी पार्टी पूरे 5 साल एनडीए गठबंधन के साथ रहेगी।

संसदीय दल की बैठक में पहुँचे चंद्रबाबू नायडू

संविधान सदन में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता वाले गठबंधन को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। बैठक में पहुंचे नायडू ने सभी सांसदों का स्वागत करते हुए कहा कि एनडीए की जीत सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुई है। उन्होंने बिना रुके और थके हुए पूरे चुनाव में कड़ी मेहनत की। उन्होंने दावा किया कि आंध्र प्रदेश में पीएम की रैली के बाद ही टीडीपी को चुनाव में इतनी बड़ी जीत मिल सकी है। पिछले 10 वर्षों में एनडीए की सरकार में हुए विकास कार्यों को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि सरकार की नीतियों के कारण देश का पूरे विश्व में सम्मान बढ़ा है। नायडू ने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि जरूरत के समय में देश को प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता मिला है। यदि हम इस मौके को गंवाते हैं तो यह देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा।

6 महीने से 1 साल के भीतर हो सकते हैं मध्यावधि चुनावः भूपेश

कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव परिणामों का स्वागत करते हुए कहा कि जनता ने पार्टियों को तोड़ने वालों, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने और उन्हें धमकी देने वालों को अच्छा सबक सिखाया है। मोहला मानपुर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने नई एनडीए सरकार के बारे में भविष्यवाणी की और सभा को तैयार रहने के लिए कहा। भूपेश बघेल ने एक्स पर वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने इसके साथ ही लिखा कि कार्यकर्ता साथी तैयार रहें! 6 महीने- 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। फडनवीस इस्तीफ़ा दे रहे हैं, योगी जी की कुर्सी डोल रही है। भजनलाल शर्मा भी डगमग-डगमग कर रहे हैं। बघेल ने कहा कि सरकार बनी नहीं है लेकिन जदयू प्रवक्ता अग्निवीर योजना रद्द करने और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ये सब वो मुद्दे हैं जो राहुल गांधी जी लेकर चले हैं।

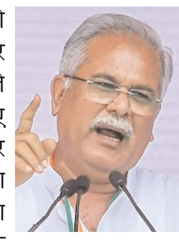

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी को शुक्रवार को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद राजग के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और फिर नरेन्द्र मोदी रविवार को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। संसद भवन की पुरानी इमारत में स्थित संविधान कक्ष में राजग की बैठक की औपचारिक शुरुआत होने के बाद वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने मोदी को राजग संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी सहयोगी दलों ने अनुमोदन किया। अनुमोदन के बाद सभी नेताओं ने ध्वनि मत से मोदी को अपना नेता चुन लिया। भाजपा और राजग नेताओं ने माला पहनाकर नेता चुने जाने पर मोदी को बधाई दी। इस दौरान कक्ष में मौजूद नेताओं ने मोदी-मोदी के नारे भी लगाए। सिंह के प्रस्ताव का सबसे पहले अमित शाह, फिर नितिन गड़करी और उसके बाद राजग के अन्य सहयोगी दलों के नेताओं ने समर्थन किया। समर्थन करने वाले प्रमुख राजग नेताओं में सबसे पहला नाम जनता दल (सेक्युलर) के एच डी कुमारस्वामी का था। इसके बाद तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता एन चंद्रबाबू नायडू और फिर जनता दल (यूनाइटेड) के नीतीश कुमार ने मोदी को राजग संसदीय दल का नेता चुने जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार सहित राजग में शमिल अन्य घटक दलों के नेताओं ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चिराग पासवान, हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा (सेक्यूलर) के जीतन राम मांझी, अपना दल (सोनेलाल) की अनुप्रिया पटेल और जन सेना पार्टी के पवन कल्याण सहित अन्य नेताओं ने भी प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

राहुल लोस चुनाव के 'मैन ऑफ द मैच', बनना चाहिए नेता प्रतिपक्ष

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव का मैन ऑफ द मैच बताया और चुनाव में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन का श्रेय उन्हें दिया। थरूर ने आगे कहा कि यह उचित होगा यदि गांधी संसद में विपक्ष के नेता का पद संभालें। लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम से लगातार चौथी बार चुनाव जीतने वाले थरूर ने कहा कि जनादेश का संदेश यह है कि मतदाताओं ने भाजपा के 'अति अहंकार'' और उसके 'मेरी बात मानिये, नहीं तो रास्ता नापिये' के रवैये को अनुचित ठहराया है। क्रिकेट उपमाओं में बोलते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी निस्संदेह, वास्तव में चुनाव के मैन ऑफ द मैच थे और कई स्थानों पर कांग्रेस ने गेंद को पार्क से बाहर कर दिया। शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने (गांधी) और कांग्रेस अध्यक्ष (मल्लिकार्जुन) खड़गे ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रचार किया, लेकिन खड़गे राज्यसभा में हैं जहां वह विपक्ष का नेतृत्व करते हैं और यह उचित होगा कि राहुल गांधी लोकसभा में भी ऐसा ही करें।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिहदेव,उपमुख्यमंत्री अरुण साव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी सहित सांसद गण ने सेंट्रल हाल में संविधान को नमन किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा संविधान का सही मायने में सम्मान करने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों ने बार बार संविधान के साथ छेड़ छाड़ की है कई बार सरकार चलाते वक्त संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर कार्य किया है,लेकिन अब भाजपा और एनडीए सरकार संविधान के खिलाफ कोई काम होने नही देती और सदैव इसकी रक्षा करती रहेगी।

प्रमुख समाचार

फडणवीस के इस्तीफे पर बैठक में चर्चा नहीं हुईः अजित

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा के खराब प्रदर्शन को लेकर उपमुख्यमंत्री पद से देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर दिल्ली में राजग की बैठक में चर्चा नहीं हुई। भाजपा के सहयोगियों-तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री एवं जद (यू) प्रमुख नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम का अनुमोदन किया। दोनों दलों ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाने का भी संदेश दिया। दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए अजित पवार ने कहा कि उपमुख्यमंत्री पद से फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश भाजपा का आंतरिक विषय है और दिल्ली में राजग की बैठक में इस पर चर्चा करने की कोई वजह नहीं थी। अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक सीट पर जीत मिली है। महाराष्ट्र में भाजपा की सीट संख्या पिछले लोकसभा चुनाव के 23 से घटकर नौ पर आने के बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं ने चुनाव बाद के परिदृश्य पर चर्चा के लिए नागपुर में फडणवीस के आवास पर उनसे मुलाकात की।

लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मुश्किल में लालू यादव

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ निर्णायक आरोप पत्र दायर किया है। इस आरोपपत्र में 78 आरोपी व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें 38 उम्मीदवारों के साथ-साथ कई अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं। इसके अलावा, सीबीआई ने अदालत को सूचित किया है कि उसे अभी भी सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी का इंतजार है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोप पत्र पर विचार के लिए मामले को 6 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। 29 मई को, सीबीआई को नौकरी के बदले भूमि मामले में अपना निर्णायक आरोप पत्र/चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने समय देने के बावजूद निर्णायक आरोपपत्र दाखिल न किए जाने पर भी नाराजगी जताई थी। 4 अक्टूबर, 2023 को, अदालत ने नौकरी के बदले भूमि घोटाले के कथित मामले में नई चार्जशीट के संबंध में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को जमानत दे दी थी।

संसद सुरक्षा में चूकः पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को संसद सुरक्षा भंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें अपनी प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। 1000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों - मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद - के संबंध में जांच पूरी हो गई है। हालांकि, आगे की जांच अभी भी जारी है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड प्रताप सिंह ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी का इंतजार है, जिसके लिए दो सप्ताह की अवधि के भीतर पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। सभी आरोपियों को उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर कोर्ट के समक्ष शारीरिक रूप से पेश किया गया। अदालत ने सभी छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी और पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के लिए मामले को 15 जुलाई को सूचीबद्ध किया।

आलोचना करने वाले पादरी पर विजयन ने किया पलटवार

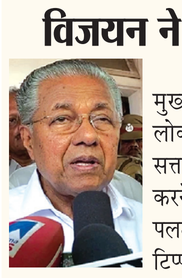

तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोकसभा चुनाव में हार चुके सत्तारूढ़ वाममोर्चा की आलोचना करने पर शुक्रवार को एक पादरी पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां दर्शाती हैं कि पादरियों में भी 'अज्ञानी व्यक्ति' हो सकते हैं। 'मलानकारा जैकोबाइट सीरियाक ओर्थोडॉक्स चर्च' के पूर्व 'मेट्रोपोलटिन ऑफ निरानाम डाइसीज' जीवर्गीज कूरिलोस ने फेसबुक पर अपने पोस्ट में कहा था, ''बाढ़ और महामारी हमेशा बचाने के लिए नहीं आती हैं तथा केरल में लोग 'किट राजनीति' में एक बार से अधिक नहीं फंसेंगे।'' केरल में 2021 में वाममोर्चा सरकार के फिर सत्ता में लौटने पर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों में मुफ्त खाद्य किट बांटे जाने के कारण ही ऐसा हो पाया है। अपने वामपंथी रूझान के लिए चर्चित पादरी कूरिलोस ने लोकसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की हार के सिलसिले में फेसबुक पर यह टिप्पणी की थी। उनकी फेसबुक टिप्पणी का हवाला देते हुए विजयन ने कहा कि इन पादरी के मुताबिक एलडीएफ को राज्य में बाढ़ के कारण सत्ता में दूसरा कार्यकाल मिला.

मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली आएंगे मुइज्जू

नई दिल्ली। चल रहे तनाव के बावजूद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने रविवार (9 जून) को नई दिल्ली दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मिहारू न्यूज के अनुसार, मुइज्जू उस समारोह के लिए शनिवार को नई दिल्ली दिल्ली के लिए रवाना होंगे जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल का प्रतीक होगा और उनके साथ कई अन्य सरकारी अधिकारी भी होंगे। हालाँकि, मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से मुइज्जू की पहली आधिकारिक भारत यात्रा के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मुइज्जू ने बुधवार को पीएम मोदी को बधाई दी थी और कहा था कि वह द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नेता के साथ काम करने को उत्सुक हैं। मुइज्जू ने पीएम मोदी के दोबारा चुने जाने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता के लिए बधाई।

18 वीं लोकसभा के चुनावों के जनादेश के मायने

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

18 वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि मतदाता के मन को समझना इतना आसान नहीं हैं। इसी तरह से एक्जिट पोल के परिणामों और धरातलीय परिणामों में अंतर से साफ हो जाता है कि मतदाता खुलता भी नहीं है तो किसके पक्ष में मतदान करके आया है उसे वह मुखर होकर बताता भी नहीं है। चुनाव परिणामों से सट्टा बाजार की भी पोल खुल कर रह गई है। ऐसे में सवाल यह हो जाता है कि मतदाता इस जनादेश के माध्यम से आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव परिणामों से यह तो साफ हो गया है कि मतदाता ने एनडीए को तीसरी बार सरकार चलाने या यों कहें कि कंटिन्यूटी का अवसर दे दिया है क्योंकि एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। ऐसा नहीं है कि परिणाम के बाद किसी बाहरी दल के सहयोग की आवश्यकता हो। बहुमत के 272 की तुलना में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं वहीं पिछले दो चुनावों की तरह इस बार भाजपा को अकेले स्पष्ट बहुमत के आंकड़ें से दूर अवश्य रखा है पर सबसे बड़े दल के रुप में भाजपा सामने आई है। देखा जाए तो 10 साल बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इससे यह भी तो स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता विरोधी लहर उतनी नहीं रही जितनी दस साल के शासन के बाद सामान्यतः आ जाती है पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा आदि के माध्यम से मतदाता ने अपनी नाराजगी जाहिर करने में किसी तरह का संकोच भी नहीं किया है। दरअसल जनआंकाक्षाओं और सरकार की परफारमेंस के बीच अंतर को पाटने में सरकार पूरी तरह से सफल नहीं रही। हांलाकि परफारमेंस के पेरामीटर्स या यों कहें कि मापदण्ड बदलते रहते हैं। एक बात यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह मेंडेंट केन्द्र सरकार की वर्तमान नीतियों का नकार नहीं हैं अपितु मतदाता सरकार द्वारा नेपथ्य में ड़ाले हुए विषयों को सामने लाकर आगे बढ़ने की दिषा में दिया गया संदेश है। और साफ है कि सरकार की प्राथमिकता में इन विषयों को लेना ही होगा।

दरअसल जनता कहीं ना कहीं संतुलन चाहती हैं। सरकारों को जहां एग्रेसिव होना अच्छा लगता हैं वहीं जनता कहीं ना कहीं डिलीवरी सिस्टम को लेकर भी चिंतित रहती है। केवल उज्जवल और एग्रेसिव छवि, सफल विदेश नीति, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, धर्म, आर्थिक विकास या यों कहें कि इकोनोमिक ग्रोथ के साथ ही बहुत से ऐसे कारक है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया का सबस बड़ा और सफलतम लोकतंत्र हमारे यहां है। लोकतांत्रिक देषों में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला भी हमारा ही देश है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था व चुनाव व्यवस्था की सारी दुनिया कायल है। पर इसके साथ ही अब आमजन का मनोभाव यह है कि राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए ना कि मण्डी बाजार जैसी एक दूसरे पर छिंटाकशी के हालात। वास्तविकता तो यह है कि प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा तो रही ही नहीं है अपितु दिन प्रतिदिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ही एकमात्र काम रह गया। मानों या ना मानों पर आज हालात यह हो गए हैं कि राजनीतिक शालिनता तो रही ही नहीं। दूसरी बात धर्म की करें तो उत्तर प्रदेष में अयोध्या की सीट पर बीजेपी उम्मीद्वार की हार और यूपी के परिणाम बीजेपी के लिए घोर निराशाजनक होने से साफ संकेत हैं कि केवल श्रीराम लला या धर्म के नाम पर ज्यादा दिन नहीं चला जा सकता। लोगों का मानना है कि अब राम मंदिर बन गया वह सबके सामने हैं तो अब उसे जनमानस की आस्था का केन्द्र रहने दो नाकि उसे राजनीतिक रुप से भुनाना। हिन्दी बेल्ट के परिणाम इसे साफ कर देते हैं। लोग आतंकवादी गतिविधियों व असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम को तो उचित मानते हैं पर अब इसमें धर्म का प्रयोग कुछ अति ही लगने लगा है। एक अन्य बिंदु आर्थिक एजेण्डा को लेकर है। कहीं भी मतदाता ने आर्थिक एजेण्डें को नकारा नहीं हैं। पर लोग अब महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं तो बाजार पर सरकार के नियंत्रण कम होने से परेशान है। जनमानस जहां आर्थिक क्षेत्र में हाई ग्रोथ चाहने लगा है तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार के अवसरों को लेकर है। पक्ष व विपक्ष सभी का प्रिय मुद्दा नौकरियां है। सरकार जहां कहती है कि लाखों की संख्या में नौकरी के अवसर विकसित किए हैं वहीं विपक्ष नौकरियां नहीं मिलने की बात करता रहा है। इन चुनावों में भी हिंदी बेल्ट में नौकरियों की कमी का अण्डर करंट अवश्य रहा है। इसलिए नौकरियों के अवसर विकसित करने के साथ ही नौकरियां उपलब्ध कराने और उसका प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आम आदमी का जीवनयापन आसानी से हो सके.

करोड़ों की सड़क पर कौड़ी भर ईमानदारी की कमी

सड़क अपनी दुर्दशा पर बहा रही है आंसू, खुद ही बयां कर रही है अपनी हालत

धमतरी। सड़क विकास का आईना होती हैं। सड़क किसी भी इलाके को विकास की ओर ले जाने का माध्यम होती है। लेकिन धमतरी में ऐसी सड़क बनीं जो खुद ही चीख-चीख कर ये कह रही है कि हां मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे ठेकेदारों ने कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया है। मेरा कोना-कोना मेरे साथ हुए अत्याचार की कहानी बयां कर रहा है। मेरी शान भी निराली होती, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने जो हरकत मेरे इज्जत के साथ की उसकी माफी नहीं दी जा सकती। मुझे देखने वाले मेरा इस्तेमाल करने वाले मुझे ही गालियां बक रहे हैं। जिन लोगों के ऊपर मेरी इज्जत को समाज में फैलाने की जिम्मेदारी थी,उन्हीं लोगों ने मेरा इमान लूट लिया है।

ऊपर लिखे गए शब्द उस सड़क के हैं, जो धमतरी शहर की शोभा बढ़ाने के लिए बनीं। लेकिन भ्रष्टाचारियों ने सड़क को ऐसा बनाया कि वो अपनी दुर्दशा पर खुद ही आंखें बहा रही है। धमतरी शहर को राहत देने के लिए बाईपास एक तरफ बनकर तैयार हुई तो दूसरी तरफ शहर के अंदर पहले से मौजूद करीब 7 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग उठी। चुनाव के वक्त सरकार पर दबाव बना और भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते ही इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति दे दी। करीब साढ़े 13 करोड़ रुपए का फंड मंजूर हुआ। इसके बाद सड़क का ठेका मित्तल कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया।

छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सड़क का काम शुरु हुआ। मित्तल कंस्ट्रक्शन ने संबलपुर बाईपास मोड़ से लेकर श्यामतराई बाईपास मोड़ तक शहर के अंदर की करीब 7 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों तरफ पाई में मुरुम फीलिंग भी किया जाना था। लेकिन निर्माण के बाद ही ये सड़क उखड़ने लगी है।भारी वाहनों का दबाव भी सड़क ना झेल पाई।जितने भारी वाहन इस सड़क से गुजरते उतनी ये सड़क धंसती जाती।आज ये सड़क उबड़ खाबड़ जमीन जैसी लगती है।जगह-जगह पर पिचक गई है।

7 किलोमीटर लंबी सड़क में सड़क किनारे की फीलिंग के लिए कहीं मुरुम डाला गया है,तो कहीं खाली छोड़ दिया गया है।कुल मिलाकर सड़क की औपचारिक मरम्मत की गई है।अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इतनी घटिया सड़क की मरम्मत करने के बाद ठेकेदार को किस चीज का पैसा सरकार ने दिया है। बहरहाल धमतरी कलेक्टर ने इस शिकायत को संज्ञान में लिया है और जांच की बात कही है।

कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा मामला संज्ञान में आया है।सड़क के मरम्मत के बाद उसमें कई जगह पर गड्ढे बन गए हैं।जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

सड़क पर चलने वाले लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं।कई जगहों पर सड़क पर पुरानी सड़क से भी गहरे गड्ढे हो चुके हैं। कार का चैंबर सड़क से टकराते हुए जाता है। दुकानदारों की माने तो कई जगहों पर छोटी कार जब गुजरती है तो उनके चेचिस की टकराने की आवाज आती है।अब शिकायत के बाद देखना ये होगा कि सड़क की मरम्मत होती है या फिर बारिश के मौसम में लोगों का जीवन लेने के लिए सड़क इसी तरह से तैयार रहती है।

भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप में क्यों लागू हुआ नया नियम

बिना हेलमेट वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप में पेट्रोल पंपों पर अगर आप बिना हेलमेट पहने जाते हैं तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस की पहल पर टाउनशिप एरिया में संचालित 11 पेट्रोल पंपों ने ये नियम बना दिया है। नए नियम के तहत अगर कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल खरीदना चाहेगा तो उसे नहीं मिलेगा। इसके साथ ही चार पहिया वाहन चालक अगर सीट बेल्ट नहीं पहने रहेगा तो उसे भी पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। सड़क हादसों को रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए ये अभियान शुरु किया गया है।

लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर सरकार और आम आदमी दोनों चिंतित हैं। समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को हेलमेट पहनने की हिदायत भी दी जाती है। बावजूद इसके लोग हेलमेट पहनने से कतराते हैं। कई लोगों की दलील होती है कि वो बस दो मिनट के लिए ही बगल में जा रहे हैं। ऐसी दलील देकर वो हेलमेट नहीं लगाते हैं। बीते दिनों ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने जनहित का हवाला देकर सभी पेट्रोल पंप संचालकों से नया नियम बनाने का आग्रह किया था। नियम को लागू करने के पहले दिन ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर अपनी टीम के साथ टाउनशिप के अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर जाकर दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट तथा चार पहिया वाहन से आने वालों को सीट बेल्ट लगाने की सलाह देते नजर आए।

ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने कहा हम लगातार अभियान चलाकर लोगों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने की हिदायत देते रहते हैं। इसके बावजूद कुछ लोग हमारी हिदायत को अनसुना कर देते हैं। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए अब हमने ये फैसला लिया है। नए नियमों के तहत जो भी बिना हेलमेट पहने पेट्रोल पंप पर आएगा उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। फोरव्हीलर वाहन चालक भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए होंगे तो उनको भी पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा।

पेट्रोल पंप संचालक राहुल साहू ने कहा आज से हमारे पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट पहने आए लोगों का पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नया नियम लागू हुआ है जिसें हम प्रमोट कर रहे हैं। कर्मचारियों को भी बता दिया गया है कि वो नियम के तहत ही पेट्रोल और डीजल दें। पुसिस ने अच्छी पहल शुरु की है हम लोगों की जान बचाने के लिए उसके साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रैफिक पुलिस की मानें तो नियमों का पालन और हेलमेट लगाने से मौतों के आंकड़ों में करीब दस फीसदी की कमी आई है। फिलहाल ये नियम भिलाई टाउनशिप के 11 पेट्रोल पंपों पर लागू किया गया है। आने वाले दिनों में अगर इसका फायदा मिला तो दूसरे पेट्रोल पंपों पर भी यह नियम लागू कराया जा सकता है।

अपनी जान हथेली पर रखकर कॉलेज पहुंचते हैं विद्यार्थी

■ **प्रोफेसर समेत करीब 80 टीचरों का स्टॉफ भी परेशान**

कोरबा। रूमगड़ा से बालको जाने वाले इस रास्ते पर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है। यहां प्रोफेसर समेत करीब 80 स्टॉफ हैं। इसके अलावा करीब 400 से अधिक विद्याथी यहां पढ़ाई करते हैं। कॉलेज प्रबंधन भी बालको मैनेजमेंट के कुप्रबंधन का शिकार हैं। दरअसल बालको मैनेजमेंट द्वारा कोयला परिवहन में लगी ट्रकों के पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सड़क पर ही सैकड़ों ट्रकों को खड़ा कर दिया जाता है। जिससे कॉलेज परिसर में प्रवेश कर पाना मुश्किल हो जाता है। जाम के कारण प्रोफेसर विलंब से कॉलेज पहुंचते हैं, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

प्रोसेफर अश्वनी सिधार ने बताया कि इस मार्ग काफी समय से परेशानी बनी हुई है वाहनों के लंबी कतार के चलते लोगो की जान जाने का डर तो बना रहता है वही कई बच्चे पेपर से भी वंचित हो रहे हैं। हर 6 माह में पेपर हो रहा है, जहां अलग-अलग जगह से आते हैं। ऐसे में वो ज्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं। 800 मीटर की दूरी तय करने में कई बार एक घंटों लग जाते हैं। प्रोफेसर जगरानी तिर्की ने बताया कि कई बार जिला प्रशासन को पत्रचार किया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

अपको बता दें कि जाम लगने की वजह से आये दिन हादसे होते हैं। कुछ माह के भीतर 6 से अधिक राहगीरों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। यही वजह है कि लोग इस रास्ते पर चलने से डरते हैं। विद्याथी और स्टाफ को हर रोज अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता है। इस संबंध में कई बार जिम्मेदार अफसरों से मदद की गुहार लगाई गई, मगर हालात जस का तस का है। सड़क पर 24 घंटे भारी वाहनों का दबाव रहता है। प्रशासनिक अफसरों के साथ ही मंत्री भी जाम में फस चुके हैं, ऐसी नौबत आने पर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी सड़क पर उतर कर जाम हटाने में लग जाते हैं। बालको मैनेजमेंट को भी फटकार लगाई जाती है। मगर जब आमआदमी इस जाम के बीच फंसता है तो जिम्मेदार आंख मूंद लेते हैं। अब देखना होगा कि राहगीरों की समस्या का समाधान कब होता है।

सीआरपीएफ व आईटीबीपी के इंजीनियर्स ने चिंतावागु नदी पर बनाया 200 मीटर का रोपवे

बीजापुर। जिले के नक्सल प्रभावित पामेड़ में स्थित चिंतावागु नदी पर सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों ने रोपवे बनाया है। रोपवे बनने से जवानों और ग्रामीणों को अब बारिश के दिनों में नदी पार करने में परेशान नहीं होगी। पहली बार बस्तर के किसी गांव में सीआरपीएफ और आईटीबीपी के 22 इंजीनियर्स ने 30 दिन की कड़ी मेहनत कर 200 मीटर का रोपवे तैयार किया है। जिसका सीआरपीएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों ने आज शुभारंभ कर दिया गया है।

विदित हो कि पामेड़ की चिंतावागु नदी बारिश के दिनों में काफी शबाब पर होती है। नदी पार के दर्जनों गांवों का संपर्क टूट जाता है। ऐसे में उस इलाके में यदि किसी बीमार को अस्पताल ले जाने में काफी परेशानी होती थी। वहीं नदी के दूसरी तरफ सुरक्षाबलों का कैंप स्थित है। सामान्य दिनों में जवान नदी पार कर सर्च ऑपरेशन में निकल जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में नदी में पानी ज्यादा होने की वजह से पार करने में जवानों को भी दिक्कत होती है। ऐसे में अब सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए नदी पर करीब 200 मीटर रोपवे निर्माण कर दिया। यह भी विदित हो कि इस नदी पार के इलाके में नक्सलियों का प्रभाव वाला इलाका है। इसी इलाके में कुछ दिन पहले नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाया था और उनकी हत्या कर दी थी। जवान समय-समय पर इस इलाके में सर्चिंग पर निकलते रहते हैं।

नक्सली हमले का वीडियो आया सामने सुरक्षाबल के कैंप पर हुआ था हमला

नारायणपुर। नारायणपुर के पुलिस कैंप पर नक्सली हमले का वीडियो सामने आया है। कल शाम नारायणपुर के पुलिस कैंप पर हमला हुआ था। हमले के बाद कैंप में अफरा-तफरी मच गई। जवान मोर्चा संभालते हुए और खुद को सुरक्षित करते नजर आए। वीडियो में बम धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंप के दूसरी तरफ मौजूद लोगों ने यह वीडियो बनाया था। नक्सलियों के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। इरकभट्टी पुलिस कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया था। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद उल्टे पैर भाग गए थे।

42 छात्रों ने नीट परीक्षा में किया उत्साहजनक प्रदर्शन

दंतेवाड़ा। छू लो आसमान संस्था ने इस वर्ष नीट परीक्षा में एक उपलब्धि हासिल की है। इस परीक्षा में संस्था के 42 छात्रों ने उत्साहजनक प्रदर्शन किया है, जिसमें से 8 छात्रों को शासकीय कॉलेज में एमबीबीएस और 9 छात्रों को बीएएमएस, बीडीएस और वेटरनरी कोर्स में प्रवेश मिलने की संभावना है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने सभी सफल छात्रों और उनके पालकों को सम्मानित किया। कलेक्टर ने अपने संबोधन में छात्रों की मेहनत और संस्थान की उत्कृष्टता की सराहना करते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि छू लो आसमान संस्था की इस शानदार सफलता के लिए सभी छात्र, उनके पालक और संस्था के शिक्षक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि वे भविष्य में भी इसी प्रकार सफलताएं प्राप्त करते रहेंगे। समारोह के बाद सभी अतिथियों के लिए एक विशेष भोज का भी आयोजन किया गया, जहां छात्रों, उनके पालकों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में एसपी गौरव राय, डीईओ एसके अम्बस्ता सहित छू लो आसमान संस्था से प्रभारी अधिकारी वीएस ताटी, अधीक्षिका सैनी रविंद्र, अधीक्षक राजा पाल, मधुसूदन राव उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कोटमसर गुफा का प्रवेश द्वार 15 जून को बंद हो जाएगा

जगदलपुर। बस्तर जले के कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्रसिद्ध कोटमसर गुफा का प्रवेश द्वार 15 जून को बंद हो जाएगा। इस वर्ष समय पर मानसून आने और बारिश शुरू होने के चलते यह गुफा अपने तय समय में बंद हो रहा है, जिसे एक सितंबर को पुन- खोला जायेगा। कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान के संचालक के अनुसार यह गुफा के बारिश के मौसम में चार माह के लिए सुरक्षा के दृष्टि से बंद कर दिय जाता है। कोटमसर गुफा के अलावा कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर चल रहे बैम्बू राफ्टिंग, कायकिंग सहित अन्य एडवेंचर बारिश के शुरू होने तक जारी रहेंगे। उल्लेखनीय है पिछले दो वर्षों में मानसून की बेरूखी के चलते कुटुमसर गुफा 30 जून तक खुले रहे। लगातार दो वर्षों तक बारिश में देरी के चलते पार्क प्रबंधन ने कुटुमसर गुफा को 15 के बजाय 30 जून को बंद करने का निर्णय लिया था। पिछले वर्ष भी कोटमसर गुफा 30 जून को बंद को बंद किया गया था, जिसे एक सितंबर को पुन- खोला गया था।

1 लाख का ईनामी नक्सली आरपीसी अध्यक्ष गिरफ्तार

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत ग्राम दुलेड़ में नक्सली बैठक की आसूचना पर थाना चिंतागुफा से जिलाबल, डीआरजी एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल ग्राम दुलेड़ जंगल पहाड़ी व आस-पास क्षेत्र की ओर नक्सली धर-पकड़ अभियान हेतु रवाना हुए थे। अभियान के दौदान ग्राम कहेर दुलेड़ के जंगल से 01 नक्सली कड़ती मुत्ता उर्फ दिनेश पिता स्व. पाण्डू (जगरगुण्डा एरिया कमेटी अंतर्गत चुलेड़ आरपीसी अध्यक्ष, पदानुरूप छ.ग. शासन द्वारा घोषित ईनामी 01 लाख रूपये एवं पुलिस अधीक्षक सुकमा द्वारा पूर्व से 50 हजार रूपये घोषित ईनामी) निवासी पटेलपारा दुलेड़ थाना चिंतागुफा जिला सुकमा को गिरफ्तार किया गया है। थाना चिंतागुफा में गिरफ्तार नक्सली कड़ती मुत्ता उर्फ दिनेश का रिकार्ड की जांच करने पर उसके विरूद्व नक्सल संगठन में विगत 30-35 वर्षों से सक्रिय रहने एवं पूर्व से नामजद 04 प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध पाये जाने पर कार्यवाही उपरांत शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

चित्रकोट जलप्रपात पर 150 फिट लंबा बनेगा पुल

जगदलपुर। जिले के दर्शनीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु चित्रकोट जलप्रपात पर कैंटिलिवर स्काई वॉक कांच का पुल 7 करोड़ की लागत से बनेगा। करीब सौ फीट की ऊंचाई से वाटर फॉल की खूबसूरती को निहारने का नजारा बेहद दिलचस्प होगा। यह पुल देश का सबसे लंबा कैंटिलिवर स्काई वॉक कांच का पुल डेढ़ सौ फीट लंबा होगा। इस कांच के पुल का निर्माण बिहार के राजगीर में बने स्काई वॉक ग्लास ब्रिज की तर्ज पर होगा, जो चीन के हांगझोऊ प्रांत में बने कांच के पुल की तर्ज पर बना है। इस पुल पर एक साथ पचास लोग सैर कर सकेंगे। यह पुल स्टील के स्ट्रक्चर से बनेगा जिसमें पांच सौ टन स्टील का उपयोग होगा। इस ब्रिज के ऊपर चढने से ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में चल रहे हैं। विदित हो कि केरल के इडुक्की में वागामोन पर वर्तमान में देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर स्काईवॉक ग्लास ब्रिज है, यह पुल चालीस मीटर लंबा है, और जमीन से डेढ़ सौ फीट ऊंचा है। इसके बाद बिहार के राजगीर का ग्लास ब्रिज देश का दूसरा इस तरह का ब्रिज है।

पोड़ीदलहा जंगल में जुआरियों के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा

जांजगीर-चांपा। अकलतरा थाना क्षेत्र अंतरगत पोड़ीदलहा जंगल में पुलिस ने जुआ खेलते अलग-अलग जिले के सात जुआरियों को गिरफ्तार किया है। छ. ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत की कार्यवाही की गई है। नकदी रकम सहित दो लाख से अधिक का सामान जब्त किया गया है। जानकारी अनुसार, अकलतरा थाना क्षेत्र के पोड़ीदलहा के जंगल में लंबे समय से पैसे का दाव लगाकर जुआ खेलने की शिकायत मिल रही थी। जिस पर अकलतरा पुलिस और सायबर टीम के द्वारा सयुक्त रूप से रेड की गई। इस दौरान अन्य जुआरी भाग निकले थे। वहीं, मौके पर जुआ खेलते हुए सात जुआरी पकड़े गए, जिनके पास से 35 हजार नकदी, छह मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल, 52 पत्ती ताश को बरामद किया गया है। सभी को पकड़कर अकलतरा थाना लाया गया, जिन पर जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2)के तहत कार्यवाही की गई।

ओडिसा से सब्जी लेकर आ रही पिकअप पलटी

जगदलपुर। बकावंड थाना क्षेत्र के कुसमी गांव में एक तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। इस घटना के तुरंत बाद पिकअप में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस टीम भी मौके पर जा पहुंची। पिकअप में लदे सामान को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। बकावंड थाना प्रभारी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह 11 बजे ओडिसा से जगदलपुर सब्जी लेकर एक पिकअप निकली थी। करीब 11.30 बजे के लगभग पिकअप कुसमी के मोड़ के पास पहुंची, तभी अचानक ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद पिकअप मोड़ पर पलट गई। इस घटना के बाद ड्राइवर किसी तरह से बाहर आ गया, लेकिन अचानक से गाड़ी में आग लग गई। वहीं, आसपास से गुजरने वाले लोगों के साथ ही बकावंड पुलिस मौके पर पहुंची।

जालसाजों ने शिक्षक के खाते से उड़ाए चार लाख रुपये

■ **व्हाट्सएप पर लिंक भेज ऐसे की ठगी**

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला में साइबर ठग ने शिक्षक के खाते से चार लाख रुपये उड़ा लिये। साइबर ठगों ने बैंक का कर्मचारी बनकर क्रेडिट कार्ड की राशि का तुरंत भुगतान करने के लिए भेजे गए लिंक को डाउनलोड करवाकर शिक्षक के खाते से चार लाख 500 रुपये निकाल लिये। शिक्षक के खुद के ठगे जाने का अहसास थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तत्काल पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, ठगों ने आईसीआईसीआई बैंक का कर्मचारी बनकर शिक्षक को व्हाट्सएप मैसेज में लिंक भेजा और उसके बाद मोबाइल पक फोन करके शिक्षक से एक लिंक डाउनलोड कराया। जिसके बाद शिक्षक के खाते से चार लाख 500 रूपये निकाल लिये।

जीपीएम जिले के सुभाष चंद्र कॉलोनी पुराना गौरेला निवासी एवं गौरेला ब्लॉक के प्रायमरी स्कूल रंजकी में पदस्थ सहायक शिक्षक पीयूष विश्वकर्मा के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आया। उस मैसेज में एक लिंक भेजा गया और उसके बाद लिंक भेजने वाले ने फोन पर बात करके पीयूष से कहा कि आपका आईसीआईसीआई बैंक से कर्ज है। उस कर्ज का किश्त आपके एसबीआई के खाते से कटकर जमा होता है। ठग ने कहा कि अब इंडसइंड बैंक आईसीआईसीआई बैंक से कनेक्ट हो गया है इसलिए क्रेडिट कार्ड के कर्ज का एक लाख रुपये का भुगतान आज ही जमा कराना आवश्यक है।

इतना कहकर ठग ने पीयूष विश्वकर्मा को भेजा हुआ लिंक डाउनलोड करने को कहा। चूंकि ठग के द्वारा फोन पर दी गई क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी सही थी, इसलिए पीयूष भी उस ठग की बातों में आ गया और उसने भेजे गए लिंक को डाउनलोड कर लिया। वहीं, लिंक को डाउनलोड करते ही पीयूष का मोबाइल फोन हैक हो गया और सभी कॉल फॉरवर्ड होने लगे। उसके बाद ठग ने पीयूष के खाते से पहले तीन लाख रुपये ट्रान्सफर किए। उसके कुछ देर बाद वो 3 लाख रुपए खाता में वापस कर दिये। इसके कुछ देर बाद ठग ने पीयूष के खाते से चार लाख 500 रूपये निकाल लिये।

जब पीयूष को खुद के साथ ठगी होने का अहसास हुआ तो उसने गौरेला थाने पहुचकर अज्ञात ठग के खिलाफ ठगी का अपराध दर्ज कराया। पीड़ित की शिकायत पर गौरेला पुलिस और साइबर सेल की टीम ठगी करने वाले के मोबाइल नंबर और जिस खाते में पैसों का ट्रांसफर हुआ सभी की तलाश करने में जुट गई है। वहीं, मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरेला पेण्ड्रा मरवाही ओम चंदेल का कहना है कि जैसे ही शिक्षक के खाते से ठगी की गई वो तत्काल साइबर सेल पहुंचे, जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल एक्टिव हो गई है सभी बिंदुओं पर जांच जारी है।

विहप एवं बजरंग दल ने निकाला जन आक्रोश मसाल जुलूस

■ **सुजीत स्वर्णकार की मौत, पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं हैं**

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर रामानुजगंज में बीते दिनों बजरंग दल के जिला सहसंयोजक सुजीत स्वर्णकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए करंट लगने से मौत होना बताते हुए मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। इसी के चलते जन आक्रोश विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। भारत माता चौक पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया।

जन आक्रोश मसाला जुलूस महामाया मंदिर के पास से निकलते हुए नगर के प्रमुख चौक-चौराहे होकर भारत माता चौक पहुंचा, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर बजरंग दल के जिला संयोजक जस्सू केसरी ने कहा कि सुजीत स्वर्णकार की हत्या हुई है, लेकिन मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान नयन गुप्ता, सूरज कश्यप, निहाल कश्यप, सुशील मेहरा आकाश ठाकुर, सौरभ श्रीवास्तव, रंजन शर्मा, प्रहलाद यादव, सूरज पासवान, कृष्णा पासवान, आर्यन गुप्ता निशान ठाकुर, शंकर शर्मा, विद्यासागर पटेल, विशाल कुमार सचिन पासवान, गौतम गुप्ता, ॠषि पासवान, आनंद विश्वकर्मा, हरिनंदन ठाकुर, सोनू पासवान, विशाल कश्यप आनंद कश्यप, अरुण कश्यप, आकाश कश्यप सहित बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

छग के सांसदों का बृजमोहन अग्रवाल ने मोदी से कराया परिचय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नव निर्वाचित दस

भाजपा सांसदों ने आज दिल्ली में एनडीए घटक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हे पुनः सरकार बनाने के लिए बधाई दी। श्री अग्रवाल ने सभी सांसदों का बारी-बारी से मोदी के संग परिचय भी कराया। श्री मोदी ने भी सभी सांसदों को उनके निर्वाचन पर शुभकामनाएं दी। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डा. रमनसिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरणदेव, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, सरोज पांडे समेत तमाम वरिष्ठ नेता भी दिल्ली में मौजूद हैं।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा

रायपुर। मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार रिट, क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, अवमानना प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का चिन्हांकन कर सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। प्रकरणों का भौतिक सत्यापन जिला न्यायालय बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग में, पदस्थ, 40 न्यायिक अधिकारियों एवं उच्च न्यायालय स्थापना में पदस्थ लगभग 36 अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य के 21 वें दिन आज गुरूवार को मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपरोक्त कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इसके दौरान मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय में चल रहें उच्च न्यायालय के भवन के आधारभूत संरचना के नवीनीकरण के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में 13 मई से 07 जून 2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है, इस दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन, निराकृत प्रकरणों का डिजीटल माध्यम अर्थात् स्केंनिग उपरान्त भौतिक सत्यापन, एवं उच्च न्यायालय के भवन के आधारभूत संरचना के नवीनीकरण के कार्यों को किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित करने की प्रणाली विकसित किया गया है ताकि ऐसे उपरोक्त चिन्हांकित लंबित प्रकरणों को सुनवाई पश्चात् निराकृत किया जा सके।

सातवें वेतनमान की अंतिम किश्त की राशि के भुगतान की स्वीकृति

रायपुर। राज्य शासन के वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने राज्य के शासकीय सेवकों के अनुरूप निगम, मंडल , आयोग, अर्धशासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को माह फरवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि के एरियर राशि के भुगतान किए जाने की स्वीकृति दे दी है।

तीन आईएएस अफसरों के तबादले

रायपुर। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को आगामी आदेश तक अस्थाई रुप से कांकेर का जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। इसी प्रकार से कांकेर के जिला कलेक्टर 2012 के आईएएस अफसर अभिजीत सिंह को गृह एवं जेल विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है तथा 2021 के आईएएस अफसर वासु जैन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सारंगढ़ को अस्थायी रुप से अवर सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के पद नियुक्त किया गया है।

डीकेएस और मेडिकल कॉलेज के कई टेंडर खत्म, चल रहे एक्सटेंशन पर

रायपुर। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल (अंबेडकर अस्पताल) और सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल (डीकेएस) के कई प्रमुख टेंडर खत्म हो गए है और एक्सटेंशन पर चल रहे है। इसमें सबसे प्रमुख किचन, लॉंड्री, डायलिसिस यूनिट और सफाई शामिल है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक ये तमाम ठेके खत्म हो गए है और आचार संहिता होने के कारण एक्सटेंशन पर चल रहे थे। लेकिन अब जल्द जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद इस टेंडरों को लेकर फैसला होने वाला है। यही कारण है कि टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इसमें शामिल होने वाले लोगों ने इसे लेने के लिए अपनी कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीकेएस अस्पताल में होने वाले तमाम ठेको का फैसला जनरल बॉडी की मीटिंग में होना है। जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इस बार अस्पताल में उक्त व्यव्यस्था मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए कैसे टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी है।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू से राज्यपाल हरिचंदन ने सौजन्य भेंट की

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें भगवान जगन्नाथ का प्रसाद और खंडुआ वस्त्र भेंट किया।

जनकल्याणकारी कार्यों में सुशासन लाने पर हुआ विचार-विमर्श

छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने सुशासन पर गठित वर्किंग ग्रुप की बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 को लेकर राज्य नीति आयोग में बैठकों और विचार-विमर्श का सिलसिला लगातार जारी है। नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में सुशासन और पारदर्शिता को लेकर हुई बैठक में सुशासन पर गठित वर्किंग समूह के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सुशासन पर गठित वर्किंग समूह की इस पहली बैठक में रोजगार, जनभागीदारी, पारदर्शिता और टेक्नालॉजी को लेकर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी तथा मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत मौजूद थे।

नीति आयोग के सदस्य श्री डॉ. के. सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन /2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित कार्य समूहों से शीघ्र जरूरी जानकारी समय सीमा में प्रस्तुत करने कहा। सुशासन और अभिशरण विभाग के सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर विकसित छत्तीसगढ़ और सुशासन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने देश के जाने-माने विशेषज्ञों के साथ

बौद्धिक विचार-विमर्श किया। आईआईएम रायपुर में हुए इस बौद्धिक विचार-विमर्श में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विशेषज्ञों ने अपने विचारों को साझा किया। इस चर्चा में गुड गवर्नेंस की महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

नीति आयोग में आयोजित बैठक में सुशासन के लिए निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों, प्रमुख चुनौतियों तथा विभागीय विजन संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी ने भी विजन डाक्यूमेंट के संबंध में सुशासन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य रखे। विधि विभाग के सचिव श्री रजनीश श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में सुशासन के लिए काननू व्यवस्था, विधि-विधायी संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी. ने विभागीय गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। योजना एवं आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद ने भी छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट के लिए विभाग के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रस्तुत किया। इसी तरह से नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों ने विजन डाक्यूमेंट के संबंध में विभागीय जानकारी प्रस्तुत की।

वर्किंग ग्रुप की बैठक में नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विधि विधायी कार्य विभाग, चिप्स के अधिकारी, राज्य नीति आयोग के सलाहकार संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित नीति आयोग के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिलों के कलेक्टर और एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सदस्यों के बीच सुशासन के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

शिवाजी प्रतिमा स्थल का किया जाएगा सौंदर्यीकरण : पुरंदर

रायपुर। शिवाजी महाराज एक ऐसे साहसी और संकल्पित योद्धा थे, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में हिंद स्वराज्य के संस्थापक के रूप में कई ऐतिहासिक कार्य किए। 6 जून, 1674 को अपूर्व भव्यता के साथ वह छत्रपति, सर्वोच्च संप्रभु के रूप में सिंहासन पर बैठे। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे इस संप्रभु और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की नींव पड़ी। उक्त बातें राजधानी रायपुर के तात्यापारा चौक पर आयोजित शिवाजी महाराज कू 351वें राज्याभिषेक समारोह में बतौर मुख्य वक्ता महाराष्ट्र मंडळ के आजीवन सभासद उदय रावले ने व्यक्त किए।

शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का जीवंत वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी ने एक ऐसे स्वदेशी साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें प्रजा का हित संरक्षण सर्वोपरि था। उन्होंने 1646 में आदिल शाही सल्तनत को चुनौती देते हुए तोरण किले पर कब्जा कर लिया। इस साहसिक विजय ने

मुगल साम्राज्य और आदिल शाही सल्तनत जैसी दुर्जेय शक्तियों को स्तब्ध कर दिया था। शिवाजी के नेतृत्व में उनकी सेना ने युद्ध में अनूठी रणनीतियों का प्रयोग किया। उनके अपरंपरागत गुरिल्ला युद्ध (गनीमी कावा) की रणनीति और जांबाजी युद्ध के मैदान में उनकी जीत की आधारशिला थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि तात्यापारा चौक स्थित वीर शिवाजी प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए वे नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। वहीं शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को शासकीय अवकाश घोषित करने के लिए वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करेंगे।

हाई कमान जो भी लें निर्णय हमें स्वीकार : टंकराम वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही साय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच मंत्री टंकराम वर्मा ने कैबिनेट में बदलाव को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इसपर कुछ नहीं कह सकते। हाई कमान जो निर्णय लेते हैं, वह हमें स्वीकार होता है। हमें जो भी जिम्मेदारी मिल जाए उसे निभाते हैं, कार्य करते हैं। लगन और ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करते हैं।

लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आए कांग्रेस की अंतरकलह को लेकर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, बीजेपी की जीत का कारण प्रधानमंत्री की उपलब्धियां है। जनकल्याणकारी योजनाओं का यह परिणाम है। विधानसभा चुनाव में घोषणाएं की गई, उसे सत प्रतिशत लोगों तक पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री ने किया। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन से भाजपा को जीत मिली। इसका असर प्रदेश में अच्छा रहा।

केबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में सुचिता होनी चाहिए। पद का मान-सम्मान होना चाहिए। असंसदीय शब्दों के प्रयोग के कारण कांग्रेस डूब गई।

वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद केंद्रीय मंत्री बनने की संभावना पर कहा, कि हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। छत्तीसगढ़ से केंद्र में ज्यादा मंत्री होंगे तो गर्व की बात है।

जीएसटी कमिश्नर से मिले व्यापारी, नोटिस व ई-वे बिल से संबधित सुझाव पर सौंपा ज्ञापन

पूर्व में जारी अधिसूचना को यथावत रखे जाने की मांग

रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया कि आज कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी जी के नेतृत्व में कैट का एक प्रतिनिधी मंडल श्री रजत बंसल (आई.ए.एस.) आयुक्त, राज्य जीएसटी, रायपुर (छ. ग.) से मुलाकात कर जीएसटी से संबधित नोटिस एवं ई-वे बिल से संबधित सुझाव का ज्ञापन सौपा गया।

कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कैट का एक प्रतिनिधी मंडल श्री रजत बंसल (आई.ए.एस.) आयुक्त, राज्य जीएसटी, रायपुर (छ. ग.) से मुलाकात कर जीएसटी एवं ई-वे बिल से संबधित सुझाव का ज्ञापन सौपा गया। I श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने ज्ञापन के माध्यम से श्री रजत बंसल (आई.ए.एस.) को अवगत कराया कि वर्तमान समय में जीएसटी विभाग से

जीएसटी से संबंधित लगभग सभी व्यापारी को नोटिस आ रही हैं, जो कि ईज़ ऑफ़ डूइंग व्यापार के विपरीत है तथा साथ ही साथ इससे व्यापारी एवं सलाहकार को चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय जीएसटी द्वारा सिर्फ़ 10 से 15 प्रतिशत व्यापारियों को नोटिस दिया जा रहा है। तथा इनकम टैक्स के अंतर्गत भी सिर्फ़ 5 प्रतिशत ही व्यापारियों को नोटिस दिया जा रहा है। जो कि न्यायोचित नहीं है। इनकम टैक्स या केन्द्रीय जीएसटी विभाग के समान सिर्फ़ 10 से 15 प्रतिशत व्यापारियों को जीएसटी के अंतर्गत विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाये।

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने आगे बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों के व्यापारियों को जीएसटी विभाग द्वारा वर्तमान में जीएसटीआर-1 फॉर्म देर से दाखिल करने के हेतु जुर्माना नोटिस जारी किया गया है। साथ ही विभाग द्वारा अन्य नोटिस व्यापारियों को दिया जा रहा है। विभाग द्वारा अचानक किये गए इस कार्यवाही से व्यापारियों में भय का माहौल है जिसके कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जबकि व्यापारिक समुदाय हमेशा सरकार को उसके कर संग्रह लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में सहयोगी रहा है और नियमों के पूर्ण अनुपालन के लिए प्रयासरत है। व्यापारियों को जीएसटी विभाग द्वारा जारी जुर्माना नोटिस को स्वतः निरस्त किया जाना चाहिए।

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने आगे बताया कि महोदय पूर्व मे शासन द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस के ध्येय को प्राप्त करने के लिए 19 जून 2018 को जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-31/2018 /वाक/पाँच (46) के तहत अभी तक राज्य मे जिले के भीतर माल परिवहन करने पर ई -वे बिल जारी करना आवश्यकता नहीं था। साथ ही साथ 15 वस्तुओ (सूची संलग्न) को छोड़कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तुओ के परिवहन पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु वर्तमान जारी अधिसूचना क्रमांक 202 के कारण ई- वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित जटिलताए बढ़ जाएगी । कैट ने आयुक्त महोदय से वर्तमान में जारी अधिसूचना पर पुनः विचार करते हुए पूर्व मे जारी अधिसूचना को यथावत रखा जाना चाहिए का आग्रह किया गया। श्री बंसल ने ज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा इस विषय पर टीम कैट को सकारात्मक आश्वासन दिया ।

आयुक्त से मुलाकात में टीम कैट एवं युवा के पदाधिकारी मुख्य रूप उपस्थित रहे :- अमर पारवानी, अमर गिदवानी, जितेन्द्र दोशी, परमानन्द जैन, सुरिन्द्रर सिंह, भरत जैन, अवनीत सिंह, कन्हैया गुप्ता, जयराम कुकरेजा, नागेन्द्र तिवारी, सीए मुकेश मोटवानी, सतीश तावानिया, दीपक विधानी एवं मनीष सोनी आदि।

प्रदेश से चलने वाली 10 ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के सालेकसा-दरेकसा रेल खंड के बीच में अप एवं डाउन रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर गिर्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा। इसकी वजह से कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है। रेलवे विभाग की ओर से 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है। सात से 12 जून को पावर ब्लॉक लेकर कार्य किया जायेगा। इस दौरान ट्रेनें रद्द रहेगी।

ये ट्रेनें रहेगी रद्द

01. दिनांक 07 एवं 12 जून, 2024 को दुर्ग से छूटने वाली 08741 दुर्ग-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

02. दिनांक 07 एवं 12 जून, 2024 को गोंदिया से छूटने वाली 08742 गोंदिया-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

03. दिनांक 07 एवं 12 जून, 2024 को गोंदिया से छूटने वाली 08743 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

04. दिनांक 07 एवं 12 जून, 2024 को इतवारी से छूटने वाली 08744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेग ।

05. दिनांक 07 एवं 12 जून, 2024 को डोंगरगढ़ से छूटने वाली 08711 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

06. दिनांक 07 एवं 12 जून, 2024 को गोंदिया से छूटने वाली 08712 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

07. दिनांक 07 एवं 12 जून, 2024 को गोंदिया से छूटने वाली 08713 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

08. दिनांक 07 एवं 12 जून, 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से छूटने वाली 08714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

09. दिनांक 07 एवं 12 जून, 2024 को बालाघाट से छूटने वाली 08715 बालाघाट-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

10. दिनांक 07 एवं 12 जून, 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से छूटने वाली 08716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

मेडिकल में जाने छात्रों को काउंसिलिंग तिथि का इंतजार, प्रवेश को लेकर कड़ी स्पर्धा

रायपुर। एमबीबीएस, बीडीएस समेत अन्य कोर्स में प्रवेश के लिए छात्रों को काउंसिलिंग तिथि का इंतजार है। एनमएसी की ओर से कामन काउंसिलिंग का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। नीट परिणाम आने की संभावित

तिथि 14 जून थी,लेकिन एनटीए ने 10 दिन पहले चार जून को ही परिणाम घोषित कर दिए। इस वजह से काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि जल्द ही काउंसिलिंग की तिथि आएगी। पिछले वर्ष जुलाई में काउंसिलिंग शुरू हुई थी। इस बार मेडिकल कालेजों में प्रवेश को लेकर छात्रों में कड़ी स्पर्धा है। पिछले वर्ष अंतिम राउंड में 530 अंक वाले अभ्यर्थी को अनारक्षित वर्ग में रायपुर मेडिकल कालेज में प्रवेश मिल गया था, लेकिन इस बार उम्मीद नहीं है।

जिस तरह से छात्रों को अंक मिले हैं, उसके मुताबिक 580 अंक हासिल करने वाले छात्रों को ही रायपुर मेडिकल कालेज में प्रवेश मिल सकता है। इससे ज्यादा भी कटआफ जा सकता है। इस बार प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में एबीबीएस की सीट नहीं बढ़ेगी, पिछली बार की तरह ही 1460 सीटों में प्रवेश दिए जाएंगे।हालांकि, निजी कालेज में सौ सीटें बढने् की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 10 शासकीय और तीन निजी मेडिकल कालेज हैं।

छत्तीसगढ़ में 13 मेडिकल कालेज हैं। इनमें एमबीबीएस की 1910 सीटें हैं। इनमें से 1460 शासकीय और 450 निजी कालेजों की सीटें हैं। इसी तरह आयुर्वेद के तीन कालेज हैं। इनमें दो शासकीय और एक निजी है। सभी यूजी की कुल 430 सीटें हैं। इसी तरह बीएनवायएस और होम्योपैथी के यूजी में 50-50 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ ही राज्य में एक शासकीय और पांच निजी डेंटल कालेज हैं। इनमें बीडीएस की 600 सीटें हैं।एमबीबीएस में 15 प्रतिशत सीटें आल इंडिया कोटे के लिए आरक्षित रहती है।

क्यों हारे भूपेश बघेल? हारकर भी बने बाजीगर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सिर फुटौवल

ललित कुमार सिंह

छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने एक सीट पर सफलता हासिल की है। बीजेपी को पिछली बार की 9 लोकसभा सीटों को बचाने की चुनौती रही, जिसमें वो पूरी तरह से सफल रही। इस बार के चुनाव में वह एक सीट (बस्तर लोकसभा) और जीतने के साथ ही कुल 10 सीटें अपनी झोली में कर ली। वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। वह दो सीटों से खिसक कर एक सीट पर आ गई। कोरबा सीट कांग्रेस के खाते में रही तो बस्तर लोकसभा सीट उसके हाथ से निकल गई। यहां से पूर्व मंत्री कवासी लखमा भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप से 55 हजार से ज्यादा वोटों से हार गए।

कुल मिलाकर बीजेपी संगठन की ताकत के बल पर लोकसभा चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही। सबसे बड़ी बात ये रही कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव हार गए। वहीं अन्य वीआईपी सीटों में ताम्रध्वज साहू महासमुंद लोकसभा सीट से, शिवकुमार डहरिया जांजगीर चांपा से, कवासी लखमा बस्तर से और सरोज पांडेय कोरबा से चुनाव हार गये। वहीं रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल ने 5 लाख से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड मत से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को हराकर नया इतिहास रच दिया।

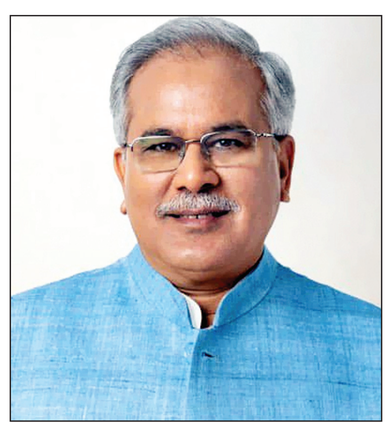

बात भूपेश बघेल की करें तो मौजूदा सांसद संतोष पांडेय ने उन्हें 44 हजार 411 वोटों से उन्हें हरा दिया। संतोष पांडे को 7 लाख 12 हजार 57 वोट मिले जबकि बघेल को 6 लाख 67 हजार 646 वोट मिले। हालांकि छत्तीसगढ़ के दूसरे सीएम रमन सिंह के गढ़ राजनांदगांव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है। चुनाव परिणाम में भूपेश बघेल भले ही हार गए हो , लेकिन राजनांदगांव सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बहुत ही बेहतर रहा है। बघेल को इस सीट पर कुल मतदान का 46.18 प्रतिशत वोट मिला है, जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भोलाराम साहू को मिले वोटों से ज्यादा है।

साल 2019 के राजनांदगांव आम चुनाव की तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में संतोष पांडे को 6 लाख 62 हजार 387 वोट मिले थे। इस बार के चुनाव में उन्हें 7 लाख 12 हजार 57 वोट मिले हैं। वहीं पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू को 5 लाख 50 हजार 421 वोट मिले थे। पांडे ने साहू को 1 लाख 11 हजार 966 वोटों से हराया था। वोट प्रतिशत 42.09 रहा। साल 2024 के चुनाव में राजनांदगाव सीट पर संतोष पांडे को कुल मतदान का 49.25 प्रतिशत वोट मिला, जो 2019 में मिले 50.65 प्रतिशत से कम है। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 6 लाख 67 हजार 646 वोट मिले हैं। इस तरह देखा जाय तो राजनांदगांव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। भूपेश बघेल चुनाव में भले ही पराजित हुए हैं , लेकिन राजनांदगांव सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से शानदार रहा है।

लोकसभा चुनाव के समय से ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सिर फुटौवल और भितरघात की स्थिति देखने को मिल रहा है। भूपेश बघेल के राजनांदगाव में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता सुरेंद्र दास वैष्णव ने उन्हें खुले मंच पर खरी-खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि की जब आप पांच साल तक प्रदेश के सीएम रहे तो आप से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। आप से मिलने के लिए तरस गये। अब जब आप सत्ता से बाहर हो गये हैं तो आप से मिलना हुआ है। इसके बाद पार्टी ने दास पर कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं पार्टी ने अन्य दो नेताओं ने भी सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर शिकायत किये थे। कांग्रेस खेमे में आपसी खींचतान, भितरघात, मनमुटाव, मनभेद और मतभेद चुनाव में हार की वजह रहे। पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव नहीं लड़ पाई।

क्या बदलने वाला है चुनाव परिणाम के बाद

बिक्रम उपाध्याय

किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि अब देश में बहुत कुछ बदल जाना है। 10 साल के बाद फिर से गठबंधन की सरकार जब चलेगी, तो फैसले उस तरह से नहीं हो पाएंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लिया करते थे। त्वरित फैसलों से होने वाले बदलाव को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा था कि भारत में कोई पॉलिसी पैरालिसिस था। उन्हीं फैसलों की बदौलत एनडीए 10 साल लगातार यह दावा करता रहा कि उसने देश का कायापलट कर दिया है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था अब तीसरे पायदान पर पहुँचने वाली है। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब केवल केवल चीन व अमेरिका से ही कुछ दूरी पर रहेगा। कहा यह भी जाने लगा था कि जिस तरह से चीन की हालिया आर्थिक परेशानियां बढ़ी हैं और उसका पतन जिस तेजी से हो रहा है, उसमें भारत का ऊपर की ओर बढ़ना और निश्चित हो गया है और वह 2030 तक चीन के काफी करीब भी पहुँच सकता है। यह सच है कि भारत की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत और संरचनात्मक रूप से ठोस नजर आ रही है। पिछले कुछ सालों में कानून प्रणाली को भी मजबूत किया गया है। कोई बड़ा भ्रष्टाचार सतह पर नहीं आया और इतनी बड़ी आबादी को राशन, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करते नहीं देखा गया। हालांकि चुनाव परिणाम यह नहीं बताते कि जनता पूरी तरह से सरकार से संतुष्ट थी। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र में मिले अवसर का लोगों ने देश की परंपरा के अनुसार अहिंसक बदलावों के लिए इस्तेमाल किया और अब एक अंकुश के साथ सरकार बनाने या चलाने का जनादेश दिया। स्पष्ट है कि इस चुनाव के बाद सरकार के काम काज के तरीके में बदलाव दिखेगा ही। हालांकि चुनावी विफलताओं के लिए केवल नेतृत्व को दोषी नहीं ठहरा सकते। वर्तमान वैश्विक परिस्थियों में किसी कमजोर सरकार का होना आंतरिक और बाहरी दुनिया में भारत की संभावनाओं को सीमित ही करेगा। आर्थिक नीतियों में कोई भी विचलन आशाजनक परिस्थितियों को निराशा में बदल सकता है, खास कर इस नजरिए से कि कई देश गहरी मंदी में हैं। आज भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के तेज़ विकास के जरिए विकासशील देशों में अपने नंबर ऊपर कर के विकसित देश होने की ओर अपनी बढ़त बनाए रखने की जरूरत है। यह तभी संभव है कि भारत के निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। पर पहले से ही कुछ घरानों के लिए काम करने के विपक्ष के आरोप के बाद सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा या फिर उसमें बदलाव होगा। चुनाव में राहुल गांधी द्वारा अदानी-अंबानी के मुद्दे उठाए गए और इन मुद्दों पर तालियाँ मिलीं भी। क्या सरकार फिर से उन्हीं मुद्दों के आगे निर्भीक रह सकेगी? भारत की सेना दुनिया में इस समय चौथी सबसे मजबूत सेना है। इसको और आगे ले जाने के लिए वित्तीय संसाधन के साथ सेना के प्रति लोगों में विश्वास और युवाओं में इससे जुडने की ललक भी जरूरी है, क्योंकि सेना भी जनसांख्यिकी प्रभावों से अछूती नहीं रह सकती। 2025 तक भारत अपनी सैन्य शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करने का ब्लू प्रिन्ट तैयार कर चुका है। लेकिन सेना में नियुक्ति को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल इन दिनों तैयार करने की कोशिश की गई। अग्निवीरों के बारे में जिस तरह के दावे किये गए और इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरह से खुलेआम कहते रहे कि सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर की योजना निरस्त कर देंगे, उससे युवाओं में असमंजस का भाव घर कर गया है। चूंकि मोदी की निवर्तमान सरकार ने अग्निवीरों में से ही नियमित सेना के जवानों की नियुक्ति का प्रावधान किया है, तो बहुत हद तक संभव है कि सैन्य नियुक्ति नियमों में भी कुछ बदलाव हो। अग्निवीरों की अभी यह शुरुआती खेप है। भारत को अपने सैन्य आधार को मजबूत करने के लिए इस योजना के प्रति युवाओं में विश्वास बहाल करना ही होगा। किसी भी संदेह की गुंजाइश भारत के लिए कुशल सैन्य शक्ति बनाने में देरी या कमजोरी का कारण बन सकती है। केवल विशिष्ट प्रौद्योगिकी विकास से ही सेना मजबूत नहीं हो सकती। किसी भी देश को एक ऐसे नेता की जरूरत होती है, जो समय और ऊर्जा देश के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास में लगा सके। उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होना चाहिए और वह अपने परिवार के लिए धन संचय करता हुआ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। इस लिहाज से नरेंद्र मोदी लगभग खरे उतरते हैं।

मोदी चला पाएंगे गठबंधन सरकार?

अजय बोकिल

लोकसभा चुनाव के झटकेदार नतीजों के कारणों का विश्लेषण राजनीतिक प्रेक्षक लगातार कर रहे हैं, पर इन कारणों में भी गजब का विरोधाभास है। बीजेपी के अपने दम पर बहुमत से काफी दूर रह जाने और कांग्रेस के बढ़कर दो गुना हो जाने का कोई ठोस कारण किसी को समझ नहीं आ रहा क्योंकि देश में अलग-अलग पॉकेट्स में अलग-अलग तरह की हवा ज्यादा दिखी। दरअसल, जो फैक्टर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, मणिपुर व राजस्थान में भाजपा की अकड़ तार- तार करते दिखे, वही फैक्टर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल और उत्तराखंड में भाजपा को मजबूत करते दिखे। भाजपा ने इसे अपनी नीतियों और जनता के विश्वास की जीत कहा तो विपक्ष ने इस जीत को मोदी व भाजपा की नैतिक हार बताकर उनसे इस्तीफा मांगा।

बहरहाल, इतना तो तय है कि देश में फीकी चमक के साथ ही सही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहां असल सवाल यह है कि क्या मोदी ऐसी सरकार को पांच साल तक चला ले जा पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि मोदी की कार्य शैली मूलत- सर्वसत्तावादी और आत्म केन्द्रित रही है। ऐसे में गठबंधन धर्म निभाते हुए सरकार को सहेजकर चलाना आसान नहीं है। इस देश में गठबंधन धर्म की ईजाद अटलजी ने की थी। क्या मोदी स्वयं में ऐसा कोई बदलाव करने के लिए तैयार हैं, खासकर तब कि जब वो अब स्वयं को परमात्मा का प्रतिनिधि मानने लगे हैं और सत्ता संचालन को ईश्वरीय कार्य।

दरअसल, 18 वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में जनता ने किसी भी एक पार्टी के बजाए एक गठबंधन के पक्ष में जनादेश दिया है। इसी के साथ देश 26 साल पुराने फिर गठबंधन सरकारों के उस दौर में पहुंच गया है, जब चुनाव से पूर्व बना समान विचारों अथवा राजनीतिक स्वार्थों वाले दलों का एक गठबंधन सत्ता में आता था तो दूसरा गठबंधन ही उसे सत्ता से बेदखल करता था। गठबंधन सरकार की अपनी हाथी की चाल होती थी। समन्वय, समझौतों, विवादों के साथ साथ विभेदक तथा दबंगई भरे मुद्दों को कालीन के नीचे सरकाते हुए सरकार चलानी होती थी। चाहे एनडीए 1 व 2 हो या फिर यूपीए 1 व 2 हो, सभी सरकारें तकरीबन उसी तरीके से चली हैं। इसके कुछ फायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे। फायदे ये थे कि ये सरकारें अमूमन अपना वजूद बचाने के लिए उन्हीं मुद्दों पर हाथ डालती थीं, जिनमें न्यूनतम राजनीतिक खतरे होते थे।

नुकसान ये था कि किसी भी गंभीर मसले पर साहसिक निर्णय लेना इनके लिए मुश्किल था। यही कारण था कि परमाणु बम विस्फोट, शाइनिंग इंडिया, भाईचारे की और पाकिस्तान से दोस्ती करने वाली अटलजी की सरकार भी आठ साल बाद आश्चर्यजनक ढंग से अचानक विदा हो गई तो उसकी जगह अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आई यूपीए सरकार रोजगार, आर्थिकी और गरीबों की बात करते करते बुरी तरह सत्ता से बेदखल हुई। उस सरकार में जनता के प्रति प्रतिबद्धता तो थी, लेकिन जनमन को रिझाने वाले फैसले लेने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी। भाजपा ने 2014 में नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर नया दांव खेला। मोदी ने जनता में उम्मीदें जगाई और स्वर्णिम भारत का सपना दिखाया। मोदीजी ने कई साहसिक (जिन्हें दुस्साहसिक भी माना गया) फैसले किए उन्हें लागू भी किया। 'सबका साथ' के नारे के साथ उन्होंने वोटों की धार्मिक गोलबंदी भी पुख्ता की। अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर निर्माण का फैसला अदालत से करवाकर मंदिर को साकार किया। नोटबंदी लागू की, जीएसटी लागू किया। तीन तलाक पर कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं का भला किया तो दूसरी तरफ मुसलमानों को नाराज भी किया।

भाजपा और आरएसएस का कोर एजेंडा कश्मीर से धारा 370 हटाई तो पड़ोसी देशों में रहने वाली गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने सीएए कानून बनाया। इसके बाद उनका इरादा समान नागरिक संहिता लागू करने का था। लेकिन यह मामला अब अधर में लटक सकता है। कुल मिलाकर यह छवि बनाई गई कि मोदी सिर्फ कहते ही नहीं, वैसा करते भी हैं। उन्होंने अपनी एक वैश्विक छवि भी बनाई साथ में अपने कट्टर हिंदू होने का संदेश भी हर पल दिया। उनके कई फैसलों से लोगों को कष्ट भी हुआ, लेकिन व्यापक हितों के संदर्भ में दस साल तक जनता मोदी को खुले मन से सपोर्ट करती रही। बावजूद इस हकीकत के कि मोदी सारा कुछ खुद ही करते हैं। वही प्रधानमंत्री हैं और मंत्री भी हैं और सचिव भी। वही संगठन के भी नियंता हैं और वही भारत के एकमेव भाग्य विधाता हैं, जिनकी नीयत पर संशय करना भी पाप है। मोदी की यह कार्यशैली विपक्ष तो छोड़िए खुद भाजपाइयों पर भी भारी पड़ने लगी थी। सत्ता और संगठन में उनका वजूद शो पीस से ज्यादा नहीं रह गया था। भाजपा व संघ का विचार मानो मोदी का विचार बन गया और पार्टी व संघ की सोच मोदी की सोच तथा गारंटी में तब्दील हो गई। 'हम' की भाषा पूरी तरह 'मैं' और उससे भी आगे सिर्फ 'मोदी' में तब्दील हो गई। प्रधान सेवक का परम पिता के रूप में यह रूपातरंण जनता देख रही थी। कुछ को उसमें देवत्व दिख रहा था तो कुछ की नजर में यह दानवत्व का बीज था।

लगता है कि विवेकशील मतदाता ने देवत्व और दानवत्व की लक्ष्मण रेखा को भांप लिया और लोकसभा चुनाव में मोदी को तीसरी बार सत्ता सौंपकर भी अंकुश अपने हाथ में रख लिया। मतदाता के मन में एक बड़ा भय लोकतंत्र के अनिष्ट का था। जनतांत्रिक व्यवस्था के अधिनायकत्व में बदलने की आशंका का था। इसमें आंशिक सचाई थी तो काल्पनिक आशंकाएं भी थीं। जैसे कि संविधान बदलकर देश को आजादी के पहले वाले दौर में ठेल देने की कोशिश, आरक्षण समाप्त करने का डर, समूची सत्ता अमीरों के हाथ में दे देने का भय, प्रतिरोध के हर स्वर को खामोश कर देने का डर तथा भौतिक विकास को ही सर्वस्व मान लेने का भ्रम भी शामिल था। अर्थव्यवस्था उड़ रही थी, गरीब का दिल बैठा जा रहा था। हिंदू एकता के नारे में जातीय और क्षेत्रीय अस्मिता और अधिकारों के खो जाने डर भी शामिल था। एक सुदृढ़ और विकसित भारत सभी देखना चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर और किसके लिए, इस पर मतभेद साफ उभर आए। यह संदेश जाने लगा कि मोदी उस तेज भागते इंजन की तरह हैं, जिसे पीछे चलने वाले डिब्बों की फिकर ही नहीं है। हालांकि मोदी ने ऐसी आशंकाओं को निराधार बताते हुए कई बार इसका खंडन भी किया। लेकिन संदेह के बादल आखिर तक छंट नहीं पाए।

सबसे बड़ा कारण तो संवादहीनता थी। भारतीय लोकतंत्र के 70 साल के इतिहास में ये पहले 10 साल थे, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवाद और समन्वय न्यूनतम स्तर पर था। यह धारणा बनी कि मोदी खुद ही फैसले लेकर बाकी लोगों को न्यायाधीश की तरह सुना देते हैं। सारी शक्तियां पीएमओ में सिमट गई थीं। मंत्री के पास फाइल पर चिड़िया बिठाने से ज्यादा कुछ बचता नहीं था। यह स्थिति भी उस लोकतांत्रिक शासन के अनुरूप नहीं थी, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। ऐसा नहीं है कि मोदी पर से पूरे देश का विश्वास उठ गया है। क्योंकि जिस संविधान के बदलने और आरक्षण खत्म होने का डर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या और कुछ दूसरे राज्यों के ओबीसी दलितों और आदिवासियों को सता रहा था, वह मप्र सहित चार राज्यों के दलित आदिवासियों को नहीं लगा। उल्टे मप्र सहित चार राज्यों में भाजपा के प्रति इन वर्गों का समर्थन और मजबूत हुआ। वैसे भी संविधान किसी विशेष राज्य या जाति के लिए नहीं बदला जा सकता।

मतदाता की खूबी यह है कि वह सत्ताधीशों के मन और नीयत को भी पढ़ लेता है। लेकिन मतदाता का शक यदि दूर न हो तो वह चुनाव में पुरस्कार या तिरस्कार के रूप में परिणत होता है। शायद इसी संभावित भय ने पूर्ण बहुमतवाली पार्टी की सरकार को अपूर्ण बहुमत वाले दल की गठबंधन सरकार में तब्दील कर दिया। यूं कहने को तो 2014 व 2019 में भी एनडीए गठबंधन की ही सरकारें थीं, लेकिन उसका समूचा नियंत्रण मोदी और भाजपा के हाथ में था। अब वैसा नहीं हो सकेगा। अगर एनडीए की सरकार पांच साल चलनी या चलानी है तो संवाद को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर तथा पारदर्शिता को दूसरे नंबर पर रखना होगा। अपने पूर्वाग्रह थोपने की जगह सबकी राय से काम करना होगा। बीते दस सालो में मोदी सरकार के कई निर्णय ऐसे थे, जिन पर फैसले से पहले ही यदि परस्पर संवाद कर आम सहमति बनाने की कोशिश की गई होती तो विवाद ही नहीं होते। तीसरा, विपक्ष का सम्मान किए बगैर सरकार चलाना नामुमकिन होगा।

यह जताना होगा कि विपक्ष के केवल एक संवैधानिक प्रावधान भर नहीं है, लोकतंत्र की एक जीवंत आवश्यकता है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि स्वयं भाजपा के अन्य नेताओं और सहयोगी दलो को भी पूरा सम्मान देना होगा, वरना कब कौन समर्थन वापस लेकर सत्ता की जाजम खींच ले, कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह सब करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा उदार, सहिष्णु और विकेन्द्रीकृत सत्ता का हामी होना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की शैली में काम करना होगा (उनकी गलतियों को छोड़कर)। क्या मोदी ऐसा कर पाएंगे, यह लाख टके का सवाल है? और इसी के साथ मोदी 3.0 पर प्रश्नचिन्ह भी!

भारतीय ज्ञान परंपरा....

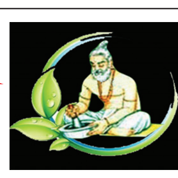

सुबालोपनिषद् (भाग-5)

गतांक से आगे...

इसी प्रकार दम (इन्द्रियदमन), दान और दया इन तीनों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा करने वाले का प्राण उत्क्रमण नहीं करता (अर्थात् अन्यत्र नहीं जाता), वरन् इस आत्मतत्त्व में ही विलीन हो जाता है और ब्रह्म होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।

हृदय के मध्यभाग में रक्त वर्ण के मांस पिण्ड के बीच वह सूक्ष्म आत्म-तत्त्व विद्यमान है। वह कुमुद (रात्रि में विकसित होने वाले कुमुद पुष्प) के समान श्वेतवर्ण वाला और अनेक प्रकार से विकसित हुआ है। हृदय में दस छिद्र होते हैं, जिनके अन्दर प्राण निवास करते हैं।

[ऋषि स्थूल हृदय के मध्य में स्थित पिण्ड में आत्मतत्त्व के होने की बात कहते हैं। वर्तमान विज्ञान के अनुसार हृदय में स्थित पेसमेकर, के साथ इसकी संगति बैठती है। हृदय की धड़कन का मूल स्पंदन वहीं से उभरता है, जिसे जीव चेतना द्वारा उद्भूत स्पंदन ही कहा जा सकता है। हृदय में 10 छिद्रों की बात स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों संदर्भों में सिद्ध होती है। हृदय की धड़कन के साथ प्राण संचरित होते हैं, 5 प्राण एवं 5उपप्राण कुल दस प्रकार के प्राणों का संचरण हृदय से होता है, यह सूक्ष्म व्याख्या हुई। स्थूल हृदय में भी 10 छिद्र इस प्रकार पाये जाते हैं- दाहिने ऑरिकल में शरीर के ऊपरी भाग से आने वाले रक्त का छिद्र सुपीरियर वैनाकोवा तथा 2. नीचे से आने वाले के लिए इन्फीरियर वैनाकोवा 3. दाहिने आरि0 से दाहिने वेंट्रिकल का छिद्र, 4. दायें वेंट्रिकल से फेफड़ों से रक्त जाने का मार्ग ट्रंक्स, 5,6. बायें फेफड़े से बायें आरि0 में प्रवेश के दो मार्ग; 7,8. दायें फेफड़े से रक्त प्रवेश के दो मार्ग, 9. बायें आरि0 से बायें बेन्ट्रि0 में रक्त जाने का मार्ग एवं 10. बायें वेंट्रिकल से शरीर पोषण के लिए रक्त से भेजने का मार्ग।]

क्रमशः ...

विश्व महासागर दिवस

अमृता गोस्वामी

'विश्व महासागर दिवस' प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। 1992 में रियो डी जनेरियो के पृथ्वी ग्रह फोरम में विश्व महासागर दिवस मनाने का फैसला लिया गया था, उसके बाद वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता मिलने के पश्चात साल 2009 से प्रतिवर्ष विश्व भर में महासागर दिवस मनाए जाने की शुरूआत हुई।

'विश्व महासागर दिवस' महासागरों के महत्व और उससे संबंधित विषयों खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकि संतुलन सामुद्रिक संसाधनों का उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि को जानने समझने के लिए लोगों को जागरूक करता है।

यह तो हम जानते ही हैं कि समस्त विश्व महासागरों के बलबूते पर ही टिका है, पृथ्वी का लगभग 70 प्रतिशत भाग महासागरों से घिरा है। महासागरों से न सिर्फ हमारा जीवन बल्कि पूरी पृथ्वी और पर्यावरण प्रभावित होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल का लगभग 97 प्रतिशत जल महासागरों में ही है। सांस लेने के लिए हमें जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसका 70 प्रतिशत महासागरों द्वारा निर्मित होता है। महासागर धरती पर असीम जैव विविधता का भंडार है। एक अनुमान के अनुसार केवल एक महासागर के अंदर करीब दस लाख प्रजातियां उपस्थित हो सकती हैं।

जीवन में महासागरों के महत्व को समझते हुए पर हम पृथ्वी वासियों का ध्यान महासागरों के अस्तित्व को अक्षुण्ण रखने की ओर अवश्य ही जाना चाहिए। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों का असर समुद्रों पर भी दिखने लगा है। समुद्रमें ऑक्सीजन का स्तर लगातार घटता जा रहा है और तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल में भारी मात्रा में प्रदूषणकारी तत्वों के मिलने से जीवन संकट में हैं। तेलवाहक जहाजों से तेल के रिसाव के कारण समुद्री जल के मटमैला होने पर उसमें सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुँच पाता, जिससे वहाँ जीवन को पनपने में परेशानी होती है और उन स्थानों पर जैव-विविधता भी प्रभावित हो रही है। महासागरों के तटीय क्षेत्रों में भी दिनों-दिन प्रदूषण का बढ़ता स्तर चिंताजनक है। आइए इस विश्व महासागर दिवस पर संकल्प लें कि समुद्रों को साफ-सुथरा प्रदूषण रहित रखे जाने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी के साथ पूरा योगदान देंगे।

पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, पृथ्वी की सतह का यह लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है। इस महासागर की गहराई 35 हजार फुट और इसका आकार ट्राईगल यानि त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर में करीब 25,000 द्वीप हैं। इस महासागर को 'शांतिपूर्ण समुद्र' के नाम से भी जाना जाता है।

अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है, इसके पास पृथ्वी का 21 प्रतिशत से अधिक भाग है। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के 8 की संख्या के जैसा है। इस महासागर की कुछ वनस्पतियां खुद से चमकती हैं क्योंकि यहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती।

पाकिस्तान को अपनी गलती का अहसास

डॉ धनंजय त्रिपाठी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह स्वीकार किया है कि करगिल में घुसपैठ कर और लड़ाई छेड़ कर 1999 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुए लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था। नवाज शरीफ तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। जब 21 फरवरी, 1999 को दोनों नेता लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब पाकिस्तानी सेना करगिल में घुसपैठ कर रही थी।

इसका नतीजा लड़ाई के रूप में सामने आया और पाकिस्तानी सेना को पीठ दिखा कर भागना पड़ा था। उस समय परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे और बाद में नवाज शरीफ को तख्तापलट में अपदस्थ कर राष्ट्रपति बने थे। भारत ने गलती मानने के इस बयान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और कहा है पाकिस्तान में करगिल मसले पर सही समझ उभर रही है। नवाज शरीफ पहले भी अनेक बार कह चुके हैं कि पाकिस्तानी सत्ता द्वारा वाजपेयी को धोखा दिया गया था, लेकिन इस बार बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह बात उन्होंने अपनी पार्टी की शीर्ष बैठक में कही है। उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग सत्तारूढ़ दल है और वे इसके अध्यक्ष हैं तथा उनके भाई शहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री हैं।

नवाज शरीफ का बयान यह स्वीकार करने का संकेत भी है कि भारत के साथ संबंध खराब रख कर पाकिस्तान की उन्नति नहीं हो सकती है। राजनीतिक निर्वासन से उनकी वापसी के बाद से यह उम्मीद लगायी जा रही थी कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार का दौर शुरू होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से खराब स्थिति से गुजर रही है। चुनाव में भी यह प्रमुख मुद्दा था। तब यह समझ उभर रही थी और सेना को भी लगने लगा था कि भारत के साथ आर्थिक संबंध ठीक करना होगा तथा पाकिस्तान को दक्षिण एशिया के साथ जुड़ना होगा। आज सभी पड़ोसी देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध खराब हैं। ऐसे में उसे यह भी समझ में आने लगा है कि वैश्विक स्तर पर भी वह महत्वहीन हो गया है और उसका दोहरा चरित्र सबके सामने स्पष्ट हो चुका है।

अगर पाकिस्तान को नये सिरे से कूटनीतिक पहल करनी है, तो यह जरूरी हो जाता है कि वह भारत के साथ रिश्ते बेहतर करे। यदि उसकी ओर से इस दिशा में प्रयास होता है, तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना भी होगी। पाकिस्तान यह भी देख रहा है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत का महत्व बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था में भी प्रगति हो रही है। इस माहौल में अगर उसे नये सिरे से कूटनीतिक पहल करनी है, तो यह जरूरी हो जाता है कि वह भारत के साथ रिश्ते बेहतर करे। यदि पाकिस्तान की ओर से इस दिशा में प्रयास होता है, तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना भी होगी। पाकिस्तान यह भी देख रहा है कि वैश्विक परिदृश्य में भारत का महत्व बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है। उसे यह स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। ऐसे दौर में जब तमाम देश भारत के साथ संबंध बेहतर कर रहे हैं, तब पाकिस्तान के पास भारत से निकटता बढ़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

इस संदर्भ में दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। दक्षिण एशिया राजनीतिक रूप से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वह परिवर्तन यह है कि दक्षिण एशियाई देश चीन के साथ-साथ भारत के साथ भी संबंध अच्छा करना चाहते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह मालदीव फिर से भारत के साथ निकटता बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। हमारे पड़ोसी देश यह अच्छी तरह देख रहे हैं कि भारत एशिया में एक उभरती हुई शक्ति है।

इसका असर भी पाकिस्तान पर पड़ा है। चीन पर उसकी अत्यधिक निर्भरता न तो उसके हित में है और न ही पाकिस्तान के पुराने हितैषी अमेरिका को यह भाता है। यह भी है कि नवाज शरीफ की भारत में खास दिलचस्पी रही है। पहले हमने देखा कि दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद भी लाहौर समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में शरीफ भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहे। तब ऐसा लगने लगा था कि दोनों देश दीर्घकालिक सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं।

नवाज शरीफ के बयान को एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए। वहां की मौजूदा सरकार को कई दलों का समर्थन प्राप्त है। सेना की ओर से भी रिश्ते बेहतरी के लिए संकेत हैं। मुझे आशा है कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच संवाद का दौर शुरू होगा और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के प्रयास होंगे। भारत और पाकिस्तान के संबंध में सबसे बड़ा अवरोध आतंकवाद और अलगाववाद को पाकिस्तान के समर्थन एवं संरक्षण के कारण रहा है। अब पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है कि वह भारत को क्षति पहुंचाये।

असल में आतंक से सबसे अधिक त्रस्त आज पाकिस्तान ही है। वहां के लोगों, नीति-निर्धारकों तथा रणनीतिक विद्वानों को यह अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि पड़ोसी देशों में आतंकवाद और अलगाववाद को हवा देने की पाकिस्तान की नीति लंबे समय तक कारगर साबित नहीं हो सकती है, बल्कि उससे देश को ही नुकसान हुआ है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी विश्वसनीयता बहुत कम हुई है। इसलिए उस नीति को बदलने की जरूरत है और ऐसा होगा भी। भारत-पाकिस्तान संबंधों में सुधार से दक्षिण एशिया को ही नहीं, बल्कि समूचे एशिया को लाभ होगा। इस दिशा में बड़े पहलों की आशा और संभावना बन रही है।

आज का इतिहास

1935 सैम पार्क्स, जूनियर ने यू.एस. ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता।
1937 जर्मन डाक मंत्रालय ने आदेश दिया कि सभी गैर-आर्यों को रिटायर करना चाहिए।
1937 अमेरिका में न्यूयार्क शहर के एक बोटेनिकल गार्डन में दुनिया का सबसे बड़ा फूल खिला।
1940 93वें तत्व नेपप्टुनियम की खोज की घोषणा की गई।
1949 उन्नीस अस्सी-चार, ओसिया के काल्पनिक अधिनायकवादी कानून के तहत जीवन के बारे में अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल द्वारा एक डायस्टोपियन राजनीतिक उपन्यास पहली बार प्रकाशित हुआ था।
1949 स्याम का नाम बदलकर थाईलैंड किया गया।
1950 थॉमस ब्लेमी मार्शल के पद को प्राप्त करने वाले एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई बन गए।
1950 सर थॉमस ब्लेमी ऑस्ट्रेलियाई के इतिहास में फील्डमार्शल बने।
1953 एक ही तूफान की वजह से दो बवंडर फ्लिंट, मिशिगन और वॉर्सेस्टर, मैसाचुसेट्स में 200 से अधिक लोगों को मार डाला, दो शहरों मोरीथन 650 मील (1, 050 किमी) के अलावा।
1963 अमेरिकी हृदय संघ एजेंसी सिगरेट के विरोध में अभियान चलाने वाली पहली एजेंसी बनी।
1972 वियतनाम वॉर-एसोसिएटेड प्रेस फोटोग्राफर निक यूट ने अपने पुलित्जर पुरस्कार विजेता ने नग्न नौ साल के फान थिए किम फुकेरिंग की नग्नता से जलने के बाद एक नग्न नग्न तस्वीर खींची।
1982 ब्राजीली विमान बी-727 दुर्घटनाग्रस्त होने से 135 लोगों की मौत हुई।
1986 पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर्ट वाल्डहेम ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति चुने गए।
1992 पहला विश्व महासागर दिवस मनाया गया। यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, रियो डी जनेरियो, ब्राजील द्वारा कनाडा द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी।
1992 ब्राजील में पहली बार वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया।
1996 10 वीं यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप (यूईएफए यूरो 96) इंग्लैंड में शुरू हुई

नीतीश और नायडू की कठपुतली सरकार बनेगी

अजय सेतिया

भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जीत का जश्न थोड़ा फीका था। भाजपा दफ्तर पहुंचे दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरों पर वैसी खुशी नहीं थी, जैसी सातों सीटें जीतने के बाद होनी चाहिए थी। भाजपा ने दिल्ली तो जीत ली, लेकिन देश हारते हारते बची। दस साल तक अपने बहुमत के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी एक मजबूर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी वह चमक नहीं थी, जो हर जीत के बाद भाजपा दफ्तर पहुंचने पर दिखती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं और देश को ही स्पष्ट संदेश नहीं दिया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ताकतों को भी सख्त संदेश दिया।

जहां देश के सामने मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, वहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी संदेश दिया कि दुनिया में भारत की आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक स्थिति को मजबूत करने की उनकी मुहिम में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिटविन द लाइन्स उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने भारत की बढ़ती ताकत के प्रभाव को रोकने के लिए उन्हें हराने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके, और अब भारत को विकसित बनाने के रास्ते में उनकी बाधाओं का भारत डट कर मुकाबला करने को तैयार है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रखने का संदेश देकर यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार कितनी भी मजबूर हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी, अरविन्द केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को यह साफ़ संदेश है। यह संयोग है कि मोदी की सरकार जिन बैसाखियों के सहारे चलेगी, वे दोनों ही बैसाखियाँ अनुभवी राजनीतिज्ञों की हैं।

नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं, और चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दस साल भाजपा का स्पष्ट बहुमत होने के कारण नरेंद्र मोदी को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, लेकिन अब कोई भी क़ानून, कोई भी नीति, कोई भी योजना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की सहमति के बिना नहीं चल सकती। संयोग से दोनों ही राजनीतिज्ञ बेदाग़ हैं, पन्द्रह बीस साल प्रशासन के मुखिया की भूमिका निभाने के बावजूद भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन दोनों पर नहीं लगा कि जो उन पर चिपक सकता। जगन मोहन रेड्डी ने स्किल डिवेलपमेंट घोटाले में चन्द्र बाबू नायडू को गिरफ्तार जरुर किया था, वह छह महीने जेल में भी रहे, लेकिन आरोप उन पर चिपका नहीं। लेकिन दोनों ही पल्टू राम के तौर पर मशहूर हैं।

चंद्रबाबू नायडू 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए थे। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के आने के बाद दो बार पलटी मारी है। पहले वह नरेंद्र मोदी को पीएम प्रोजेक्ट किए जाने के खिलाफ 2013 में एनडीए छोड़ गए थे, 2017 में एनडीए में लौटे तो 2019 का लोकसभा और 2020 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ने के बाद 2022 में एनडीए छोड़ गए थे। नीतीश कुमार जून 2023 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी एलायंस के आर्किटेक्ट थे। 23 जून इंडी एलायंस की पहली बैठक के आयोजक भी वही थे। तब माना जा रहा था कि विपक्षी एकता करवाने में कामयाब रहे नीतीश कुमार को इंडी एलायंस का कन्वीनर बनाया जाएगा और बाद में उन्हें ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। उन्हें कन्वीनर बनाए जाने या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने में कांग्रेस बड़ी बाधा बन गई थी, तो वह लौट कर एनडीए में आ गए। क्योंकि दोनों पल्टू राम रहे हैं, इसलिए इन दोनों पर सवाल उठ रहे हैं कि वे किसकी सरकार बनवाएंगे। चुनाव नतीजों के बाद ही खबर आई कि शरद पवार ने दोनों से संपर्क साधा है, हालांकि बाद में शरद पवार ने खंडन किया। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। जो

भी सरकार बने वह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की कठपुतली होगी, क्योंकि अठारहवीं लोकसभा का सत्ता संतुलन इन दोनों के पास है।

सवाल यह है कि अगर वे दोनों मोदी की सरकार बनवाएंगे, तो क्या उन्हें पांच साल प्रधानमंत्री बने रहने देंगे। अगर वे इंडी एलायंस की सरकार बनवाएंगे, तो क्या इंडी एलायंस की सरकार स्थिर रह सकती है। सरकार कोई भी बने, इन दोनों नेताओं पर निर्भर रहेगी। 1989 से लेकर 2014 तक रही अस्थिरता की राजनीति लौट आई है। कहने को वाजपेयी ने अपनी दूसरी टर्म और मनमोहन सिंह ने अपनी दोनों टर्म पूरी की, लेकिन दोनों मजबूरी की सरकारें थीं, और दोनों को कई समझौते करने पड़े थे। 2024 के चुनाव नतीजों के बाद उसी युग की वापसी हो गई है। 1998 में भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद तमिलनाडू की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन की चिठ्ठी नहीं दी थी। 16 फरवरी को चुनाव नतीजे आए थे, और एक महीने तक वाजपेयी अपने ही सहयोगी दल से समर्थन की चिठ्ठी हासिल नहीं कर पाए थे। 15 मार्च 1998 की सुबह अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति के. आर. नारायण को कहने जा रहे थे कि उनके पास सिर्फ 237 सांसदों का समर्थन है, वह सरकार बनाने का न्योता देना चाहते हैं, तो दें, नहीं देना चाहते, तो न दें। तभी जयललिता ने अन्नाद्रमुक और अपनी सहयोगी पार्टियों के 27 सांसदों के समर्थन की चिठ्ठियाँ भिजवा दीं। तब भी 543 के सदन में वाजपेयी को 264 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ था। चंद्रबाबू नायडू तब भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1996 से 1998 तक कांग्रेस के समर्थन से चली संयुक्त मोर्चा सरकार के संयोजक थे, उनकी तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा की 12 सीटें जीती थी। उन्होंने वाजपेयी को समर्थन नहीं दिया था।

राष्ट्रपति के. आर. नारायण ने खुद उन्हें फोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा था कि सदन में वाजपेयी विश्वास मत पेश करेंगे, तो वह तटस्थ रहेंगे। उनके इस वायदे के बाद राष्ट्रपति आश्वस्त हुए थे कि वाजपेयी बहुमत साबित करने की स्थिति में हैं, तब उन्होंने 15 मार्च की रात को वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया था। जब सरकार का गठन हो गया तो सरकार पर अपना नियन्त्रण रखने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी के पहली बार सांसद चुने गए जीएमसी बालयोगी को लोकसभा का स्पीकर बनवाया था। भले ही चन्द्रबाबू ने एनडीए के साथ रहने का वायदा किया है, लेकिन स्थिति 1998 जैसी ही है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के किसी सांसद को न सिर्फ स्पीकर पद देना पड सकता है, बल्कि एनडीए के कन्वीनर का पद भी सौंपना पड़ सकता है, जिस पर इस समय अमित शाह विराजमान हैं। मोदी ने स्थिति को भांपते हुए आंध्र प्रदेश के प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह के माध्यम से चंद्रबाबू नायडू को एनडीए का संयोजक बनने का ऑफर भेज दिया है।

2019 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए में रहते हुए चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी जेडीयू को लोकसभा में 16 सीटें मिलीं थीं, तब उन्होंने केबिनेट के दो पद मांगे थे, लेकिन जब अमित शाह इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो वह नाराज हो गए थे, उन्होंने मंत्री पद के लिए कोई भी नाम नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी ने बाद में उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य आरपी सिंह को केन्द्रीय मंत्री की शपथ दिला दी, जिस पर नीतीश कुमार इतने खफा हुए कि पहले उन्होंने उनसे अध्यक्ष पद से इस्तीफा लिया और बाद में राज्यसभा पर दुबारा नामांकित करने से इंकार करके उनकी राज्यसभा सदस्यता भी छीन ली थी।

तो सवाल यह कि अब चाबी नीतीश कुमार के हाथ में है, क्या वह अमित शाह से उनके 2019 के व्यवहार का बदला ले सकते हैं। क्या वह शर्त रख सकते हैं कि वह अमित शाह रहित सरकार का समर्थन करेंगे। अगर वह ऐसी शर्त रखते हैं तो यह मजबूरी की सरकार की शुरुआत भर होगी। अमित शाह को दुबारा पार्टी में भेज कर जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता और मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है क्या संघ अमित शाह के नाम पर सहमत होगा। नीतीश कुमार अगर ऐसी शर्त नहीं रखते है, और खुद को उप प्रधानमंत्री बनाने की शर्त रखते हैं, तो मोदी को उनकी यह शर्त भी माननी होगी। चार जून के नतीजों से पहले तो नीतीश कुमार सिर्फ यह चाहते थे कि विधानसभा को भंग करके उन्हीं की रहनुमाई में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभाओं के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं। बदली परिस्थितियों में शर्तें भी बदल सकती हैं।

खुशियों के बीच भगवा दलों का अदृश्य नुकसान...

अमिताभ श्रीवास्तव

आम चुनाव-2024 में महाराष्ट्र में जीत की खुशी में शिवसेना ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे चाहे जितनी बांछें खिला लें, लेकिन भगवा दलों के दिल पर हाथ रखकर सही हाल जाना जाए तो उनका अच्छा खासा नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस लोकसभा चुनाव में धर्मनिरपेक्ष दलों की तो लॉटरी ही खुल गई है। वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अटूट शिवसेना ने क्रमश: 25 व 23 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 23 व 18 सीटें जीती थीं। ताजा परिणामों के संकेतों को समग्र रूप से देखा जाए तो करीब भगवा दल मात्र 27 सीटें ही जीतते दिखाई दे रहे हैं। जिससे साफ है कि उन्हें आपस के झगड़े से 14 सीटों का सीधा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अब यदि ताजा चुनाव के गणित से भी देखा जाए तो भाजपा 28 सीटों पर चुनाव लड़कर आधे से कम सीटें जीतने की स्थिति में है। दूसरी ओर शिवसेना के दोनों गुटों का भी यही हाल है। इस चुनाव में सर्वाधिक लाभ कांग्रेस को होता दिख रहा है, जिसने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटें जीत लीं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट भी कांग्रेस की तरह अत्यधिक लाभ में नजर आ रहा है, जिसने दस सीटों पर चुनाव लड़कर सात सीटें अपने नाम की हैं। दोनों ही धर्मनिरपेक्ष दलों ने 19 सीटें अपने नाम की हैं। वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के चुनाव में दोनों कांग्रेस क्रमश- छह और पांच सीटें ही जीत पाई थीं। इसके साथ ही दस वर्ष के अंतराल के बाद दोनों दलों, हालांकि राकांपा को टूट का सामना करना पड़ा, को इस चुनाव ने नई संजीवनी दी है। दोनों राकांपा को एक साथ देखा जाए तो कुल 20 सीटें उनके खाते में जाती हैं। एक निर्दलीय विजेता प्रत्याशी भी कांग्रेस का असंतुष्ट ही है। इस तरह भगवा दलों के मुकाबले धर्मनिरपेक्ष दल 21 सीटों पर कब्जा करते दिखाई देते हैं, जो जीत की खुशी में उनका अदृश्य नुकसान है। फिलहाल यह चुनाव परिणाम दो की लड़ाई में तीसरे के फायदे का सबक लेने का है। वर्ष 1995 विधिवत् गठबंधन के रूप में लड़ने वाले भगवा दल शिवसेना और भाजपा के बीच मतभेदों की गुंजाइश हमेशा ही कम रही। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव तक स्थितियां सामान्य रहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद संबंध इस कदर बिगड़ गए कि लोकसभा चुनाव के परिणामों की स्थितियां ही बदल गईं। वैचारिक दृष्टि से दोनों एक ही राह पर चलने के बावजूद अलग-अलग गठबंधनों में रहकर एक-दूसरे के मतों को बांटने पर मजबूर हैं। दोनों दलों की महत्वाकांक्षा और नेतृत्व की लालसा मतदाता को भ्रमित कर रही है। नए समीकरणों के बीच भाजपा महाराष्ट्र के महागठबंधन के साथ है, जिसमें शिवसेना का शिंदे गुट और राकांपा का अजित पवार गुट है। इसमें अजित पवार गुट के अलावा शिंदे गुट से भाजपा की विचारधारा मिलती है और दोनों एक सुर में बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट के अलावा राकांपा शरद पवार और कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ ही राजनीति करते हैं। ऐसे में शिवसेना के उद्धव गुट को ताजा चुनाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। भविष्य में भी उसे अपनी सोच को स्पष्ट रूप से सामने रखना होगा। मानसिकता के विपरीत चलने में हर बार परेशानी आएगी। एक समूह के तौर पर विजय स्वयं की लगेगी, लेकिन वास्तविक रूप में बांट कर देखने में नुकसान ही समझ में आएगा।

यूपी में भाजपा की हार का कारण स्थानीय है

बद्री नारायण

भाजपा को सबसे अधिक झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। इसकी अनेक वजहें रहीं। पहली वजह तो यह है कि स्थानीय स्तर पर सांसदों के प्रति एंटी-इनकम्बेंसी थी। दूसरा कारण है कार्यकर्ताओं में उदासीनता और नाराजगी। ऐसा सभी जगह नहीं था, पर कई क्षेत्रों में यह स्थिति थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर बहुत बोझ आया क्योंकि चुनाव उसके आधार पर लड़ा जा रहा था। पहले जब भी उनकी छवि के प्रभाव में कमी होती थी, उसकी भरपाई उनके दौरों से हो जाती थी। इस बार ऐसा नहीं हो पाया। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को लामबंद करने का जो तौर-तरीका पहले भाजपा ने अपनाया था, इस चुनाव में वह समाजवादी पार्टी ने अपनाया। गैर-जाटव और गैर-यादव समुदायों को जोड़ने के इस प्रयास का लाभ विपक्ष को मिला। अब सवाल उठता है कि जब दोनों पक्ष एक ही तरीके पर चल रहे थे, तो एक पक्ष को ही उसका फायदा क्यों मिला। ऐसा इसलिए हुआ कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के खेमे में पहले के उम्मीदवार ही फिर मैदान में थे। तो उस पक्ष को एंटी-इनकम्बेंसी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण नुकसान उठाना पड़ा।

अखिलेश यादव ने इस बार टिकट बंटवारे में जो सोशल इंजीनियरिंग का मेथड इस्तेमाल में लाया, वह भाजपा का तरीका होता था। उन्होंने अधिक उम्मीदवार गैर-यादव ओबीसी जातियों से उतारे। दूसरी बात है कि सपा गठबंधन ने अपने प्रचार अभियान में मानसिक भय (फियर साइकोसिस) के इर्द-गिर्द एक मेटानैरेटिव खड़ा किया और मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। कहा गया कि अगर भाजपा की जीत होती है, तो संविधान बदल दिया जायेगा, आरक्षण में कटौती कर दी जायेगी। जब भी फीयर साइकोसिस की स्थिति आती है, जो सीमित पहचान होती है, वह जग जाती है तथा लोग बड़ी पहचान से सीमित पहचान की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी धर्म से

जाति की ओर, क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि हमारे अधिकार छीन जायेंगे। उत्तर प्रदेश के नतीजों की व्याख्या इसी रूप में हो सकती है। जहां तक रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों का सवाल है, तो ऐसे मुद्दे तो हर चुनाव में होते हैं। लेकिन नतीजों में उनका खास असर कहां दिखाई देता है! ये मुद्दे अहम हैं, लेकिन चुनावी लामबंदी को तय करने में इनकी भूमिका बहुत सीमित होती है। और अगर इन मुद्दों का असर होता, तो यह समूचे देश में होना चाहिए था।

अब यह सवाल उठता है कि उत्तर भारत के अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश जैसे नतीजे क्यों नहीं सामने आये। मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। इस बड़ी जीत के कारणों में उम्मीदवारों का अच्छा चयन और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को गिन सकते हैं। विपक्ष के पास जैसा नेता अखिलेश के रूप में उत्तर प्रदेश में था, वैसा मध्य प्रदेश में नहीं था। झारखंड में ऐसी ही स्थिति रही। वहां भाजपा के पास कोई मजबूत नेता नहीं है, जबकि विपक्ष के पास हेमंत सोरेन थे। जैसा कि कहा जा रहा था, यह चुनाव मोदी की छवि पर आधारित था और यह कारक देश के कई भागों में बहुत प्रभावी साबित हुआ है तथा भाजपा को जीत हासिल हुई है। हमने देखा कि ओडिशा में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा में भी पार्टी को बड़ी जीत मिली है और वह राज्य में सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भाजपा को निश्चित रूप से झटका लगा है। इन राज्यों के परिणामों के अलग-अलग कारण हैं, जिनकी अलग से व्याख्या की जा सकती है। यहां मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि राहुल गांधी की छवि को पहले की तुलना में बड़ी स्वीकृति मिली है।

चुनाव परिणाम की व्याख्या करते हुए हमें मतदान में महिला और दलित मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी पर भी गौर करना चाहिए। चुनाव-दर-दर चुनाव इनकी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसकी वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (इवीएम) ने इन्हें बड़ा सहारा और हौसला प्रदान किया है। पहले यह डर बना रहता था कि बूथ कैप्चरिंग हो जायेगी, कोई बक्सा लेकर भाग जायेगा, हिंसा हो जायेगी। इवीएम के आने के बाद यह डर निकल गया और परिस्थितियां भी बदल गयीं। तो, यह स्पष्ट है कि हमारे देश में इवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभायी है। वर्ष 2017 में प्रकाशित अर्थशास्त्री शमिका रवि के एक महत्वपूर्ण अध्ययन को देखा जाना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया है कि इवीएम की वजह से महिलाओं और सभी वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ी है। रही बात उनकी पसंद की, तो अलग-अलग जगहों पर महिलाओं ने भी अलग-अलग कारणों से अलग-अलग पार्टियों और उम्मीदवारों को वोट दिया है। यह जरूर कहा जा सकता है कि कल्याण योजनाओं ने महिलाओं और हाशिये के समुदायों को भाजपा के पक्ष में लामबंद करने में बड़ा योगदान दिया है। योजनाओं के लाभार्थियों के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के लगातार जुड़े रहने से भाजपा को निश्चित ही लाभ हुआ है। यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ने कई भाजपा उम्मीदवारों की संभावित हार को जीत में बदल दिया। दक्षिण भारत में इस आम चुनाव ने भाजपा के लिए संभावनाओं के नये द्वार खोले हैं। केरल में पार्टी को पहली बार जगह मिली है। केरल और तमिलनाडु में उसके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। तमिलनाडु में अब यह दो अंकों में पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसकी सीटें बढ़ी हैं।

मायावती अगर मदद नहीं करतीं तो मोदी का पीएम बनना मुश्किल होता

नीरज कुमार दुबे

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती एक समय उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाती थीं लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि अब बसपा सिर्फ वोट कटवा पार्टी बन कर रह गयी है। अपनी शर्तों पर राजनीति करतीं रहीं मायावती की पार्टी का उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक है जबकि कभी यहां उनके पास पूर्ण बहुमत हुआ करता था। मायावती ने चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का पद संभाला लेकिन आज वह अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही हैं। चुनाव विधानसभा के हों या लोकसभा के, मायावती और बसपा जिस बेमन से चुनाव लड़ते हैं उससे आरोप लगता है कि वह भाजपा की बी टीम हैं। जब अन्य दलों की तीन-चार दर्जन रैलियां हो जाती हैं तब मायावती प्रचार के लिए निकलती हैं।

इसके अलावा, हाल के वर्षों में खासकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के उपचुनावों के समय बसपा ने कई जगह ऐसे उम्मीदवार दिये जोकि विपक्षी मतों का विभाजन करवा कर भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त कर सके। इस बार के लोकसभा चुनावों से पहले मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्यौता दिया गया था लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह इंडिया गठबंधन की जीत हुई है उससे प्रतीत होता है कि यदि मायावती ने इंडिया गठबंधन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो भाजपा को और भी नीचे लाया जा सकता था। मायावती ने जब इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होकर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय किया था तब भी कहा गया था कि ऐसा वह भाजपा के दबाव में कर रही हैं। यही नहीं उनके उत्तराधिकारी और भतीजे आकाश आनंद ने जब लोकसभा चुनाव प्रचार में धुआंधार रैलिया करनी शुरू कीं और उन्हें मीडिया भी तवज्जो देने लगा तो एकदम से आकाश आनंद के पर इस बात को लेकर कतर दिये गये कि उन्होंने एक रैली में हिंसा भड़काने जैसा बयान दिया। देखा जाये तो आकाश आनंद ने जो कहा था वह गलत था लेकिन चुनावी रैलियों के दौरान विभिन्न दलों के नेता आकाश आनंद से भी ज्यादा बढ़-चढ़कर बातें कह रहे थे।

अब जबकि लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आ गये हैं तो एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि मायावती की ओर से अकेले लड़ने का निर्णय संभवत: भाजपा की मदद करने के लिए किया गया था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भले एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती हो लेकिन उसने 16 सीटों पर दूसरों का खेल बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। 16 सीटों पर बसपा को जितने वोट मिले हैं वो मुख्य प्रतिद्वंद्वियों की हार और जीत के अंतर से ज्यादा हैं। यह सभी 16 सीटें एनडीए के खाते में गयी हैं। इनमें से 14 सीटें भाजपा के पास हैं। एक सीट राष्ट्रीय लोक दल के पास और एक सीट अपना दल (सोनेलाल) के पास गयी है। कल्पना कीजिये कि यदि मायावती के उम्मीदवार मैदान में नहीं होते तो भाजपा को 240 की जगह 226 सीटें ही मिली होतीं और एनडीए का कुल आंकड़ा भी 278 सीटों का ही होता। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा जो 33 सीटें लेकर आई है यदि मायावती के उम्मीदवार नहीं होते तो यह नंबर 19 हो सकता था। मायावती ने भाजपा की किस तरह मदद की इसको समझने के लिए उत्तर प्रदेश की भदोही सीट को देखें जहां पर बसपा प्रत्याशी को 1.6 लाख वोट मिले जिसने भाजपा उम्मीदवार डॉ. विनोद कुमार बिंद की जीत का रास्ता साफ कर दिया। इसी प्रकार मिर्जापुर में अपना दल (सोनेलाल) की अनुप्रिया पटेल 37810 वोटों से जीत पाईं क्योंकि बसपा के मनीष कुमार ने 1.4 लाख वोट लेकर सपा उम्मीदवार का खेल बिगाड़ दिया। मायावती के कारण इंडिया गठबंधन के खाते में आने से जो सीटें रह गयीं उनमें अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, मिश्रिख, फूलपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव सीटें शामिल हैं। हम आपको यह भी याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भी निचले स्तर तक यह संदेश पहुँचा था कि मायावती ने अपने वोटबैंक को भाजपा की मदद करने के लिए कहा है। हालांकि इस संदेश की सत्यता प्रमाणित नहीं हो पाई थी लेकिन इसने भाजपा को भारी लाभ पहुँचाया था।

बहरहाल, यह चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि बसपा का कोर वोट बैंक दलित और जाटव अब इंडिया गठबंधन की ओर जा रहा है। बसपा के वोट बैंक में तीन फीसदी की गिरावट इस बात की जरूरत पर जोर देती है कि पार्टी नेतृत्व को अब गंभीरता से अपने भविष्य पर विचार करना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनावों में मिली 10 सीटों की बजाय बसपा का इस बार शून्य पर सिमटना, ज्यादातर बसपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना और बसपा की सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले की हवा निकलने से मायावती का भड़कना भी स्वाभाविक है। मायावती को चूंकि इस बार मुस्लिमों का वोट बिल्कुल नहीं मिला है इसलिए उनका आहत होना भी स्वाभाविक है लेकिन उनका सार्वजनिक रूप से किसी कौम को यह कहना गलत है कि कि वोट नहीं देने वालों को हम भविष्य में सोच समझ कर मौका देंगे। मायावती का यह बयान यह भी दर्शाता है कि वह भी उन नेताओं में शामिल हैं जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। देखा जाये तो तुष्टिकरण की राजनीति के लाभ अल्पकालिक ही होते हैं जिसने भी इसे अपनी राजनीति का आधार बनाया है उसकी जमीन एक ना एक दिन खिसकी ही है।

केंद्र की लोक कल्याणकारी नीतियों पर जनता ने जताया भरोसा

डॉ अश्वनी महाजन

केंद्र सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियां रहीं, उन्हें संदर्भ में लेते हुए यदि लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर शेष भारत में ये नीतियां- विशेषकर घरों का निर्माण, शौचालय का निर्माण, नल से जल, उज्ज्वला योजना आदि- कहीं न कहीं वोटों में तब्दील हुई हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि राजनीतिक समीकरणों के चलते, वोटबैंक की राजनीति के चलते, जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए थीं, उतनी नहीं मिलीं। बावजूद इसके कि वहां लाभार्थी बड़ी संख्या में थे। इस राज्य में सभी जात-बिरादरी और सभी धर्म के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला था। परंतु हम समझते हैं कि जो समाज है वह जात-बिरादरी, पूजा-पद्धति को लेकर बंटा हुआ है। वोट बैंक के द्वारा जो एकजुट होकर वोटिंग होती है, उसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि कोई अपने आपको एक जाति का कहता है, कोई दूसरी जाति का, तो कोई अपने आपको विशेष पूजा-पद्धति का मानता है। इसके चलते वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ है, उसके कारण भी कुछ हद तक ऐसे नतीजे दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में। परंतु हमें यह भी समझना होगा कि भले ही यह सच है कि कांग्रेस और इंडी अलायंस के बाकी जो पार्टनर हैं, उनको सीटों का लाभ हुआ है। पर यह भी उतना ही सच है कि 10 वर्ष तक सरकार चलाने के बाद भी लगभग 300 सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। तो इसका अर्थ यह भी माना जा सकता है कि 10 वर्षों के बाद भी जो एनडीए अलायंस अपनी सत्ता को बरकरार रखने में सफल रही है, वह अपने आप में एक इतिहास है। दस वर्षों के बाद भी एनडीए अलायंस अपनी सत्ता को बरकरार रखने में सफल रही है, वह अपने आप में एक इतिहास है। इसका कारण है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, एनडीए सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां और उन नीतियों पर लाभार्थियों का विश्वास। जो चार करोड़ घर लोगों को मिले हैं, पांच लोगों का एक परिवार माना जाए, तो 20 करोड़ लोगों को घर का सुख मिला है, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन मिला है- ऐसी तमाम योजनाएं, जिनसे लोग लाभान्वित हुए हैं, उसने लाभार्थियों की मानसिकता पर असर डाला है। इसी कारण भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए है, उसकी सरकार में फिर से वापसी हुई है। इसके बावजूद कि कांग्रेस ने एक लाख रुपये सभी परिवारों को देने का वादा किया था, फिर भी बड़ी संख्या में जनता ने अपने लोभ का संवरण करते हुए, दोबारा से एनडीए को सत्ता सौंपी है। यह भी सच है कि सरकार के दस वर्ष तक सत्ता में रहने और इंडी अलायंस द्वारा तमाम तरह के फ्रीबिज के वादों के बावजूद लोगों ने इंडी अलायंस को नकारते हुए एनडीए को सरकार बनाने का अवसर दिया है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां रहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि बनी, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में जो उछाल आया, हम दसवीं से पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गये और जनता में इस भरोसे का संचार हुआ कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, उन सबका लाभ एनडीए को मिला है। हर क्षेत्र में, चाहे वह नवाचार का हो- जिसमें एक लाख, तीन हजार पेटेंट ग्रांट किये गये, चाहे वह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का विषय हो, मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने की बात हो, उन सबका लाभ भी वर्तमान सरकार को मिला है और पुन- जनादेश भी मिला है कि वह सरकार चलाये।

पलकों पर लगे ज्यादा मस्कारा को हटाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, खराब नहीं होगा मेकअप

कई बार मस्कारा लगाने के दौरान हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। जिसके कारण हमारा पूरा लुक बिगड़ जाता है। ऐसे में आज हम आपको आंखों की पलकों की पर लगे एक्स्ट्रा मस्कारा को निकालने के लिए कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। मेकअप करना हर लड़की और महिला को पसंद होता है। इसलिए हम सभी न जाने कितने तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। लेकिन मेकअप के दौरान जल्दबाजी करने से कई बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कहीं किसी चीज को गलत तरीके से लगा लेते हैं, तो कभी किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। मेकअप के दौरान यही छोटी-छोटी गलतियां आपके मेकअप की खूबसूरती को बिगाड़ देती हैं। आई लुक का मेकअप में अहम रोल होता है और इसके लिए हमें ध्यान से मेकअप प्रोडक्ट का चुनाव व इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार मस्कारा लगाने के दौरान हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। जिसके कारण हमारा पूरा लुक बिगड़ जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको आंखों की पलकों की पर लगे एक्स्ट्रा मस्कारा को निकालने के लिए उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। जो आपके मेकअप लुक को खराब होने से बचा सकते हैं।

मस्कारा लगाने के दौरान की गई गलतियां

आईलैश को घना दिखाने के लिए हम मस्कारा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पलकों को ज्यादा घना दिखाने के लिए बार-बार मस्कारा की कोटिंग करते हैं। लेकिन बार-बार मस्कारा लगाने से पलकें घनी होने की बजाय भद्दी नजर आने लगती हैं। आईलैश पर मस्कारा की 2 से ज्यादा बार कोटिंग नहीं करना चाहिए। जिससे की आपकी आंखें खूबसूरत लगें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मस्कारा पलकों पर एक ही जगह इकट्ठा न हो पाए।

ऐसे हटाएं मस्कारा

ड्राई मस्कारा हटाने के लिए

पलकों पर लगे एक्स्ट्रा मस्कारा को हटाने के लिए कटोरी में नारियल के तेल की कुछ बूंद डालें।

फिर इस तेल में इयरबड्स को डुबोकर हल्के हाथों के दबाव का इस्तेमाल कर पलकों पर लगे एक्स्ट्रा मस्कारा को हटा सकती हैं।

पूरा मस्कारा हटाने के लिए

अगर आप पूरा मस्कारा हटाना चाहती हैं और आपकी आंखें ऑयली हैं, या मस्कारा पूरी तरह सूख गया है। तो आप मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल कर सकती हैं। मेकअप रिमूवर में इयरबड्स को डुबोकर आप आंखों की पलकों पर लगे मस्कारा को हटा सकती हैं।

ऑयली आंखों से मस्कारा हटाने के लिए

अगर आपकी आंखों का ऊपरी हिस्सा ऑयली है। तो पलकों पर लगे मस्कारा को आप गुलाब जल की मदद से हटा सकती हैं। इसके लिए भी आप इयरबड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। जिससे कि आपकी त्वचा और आंखों को नुकसान भी न पहुंचे और आप आसानी से मस्कारा भी हटा सकें।

शोधकर्ताओं को क्लिनिक ट्रायल में मिले सकारात्मक परिणाम

शोधकर्ताओं ने पुरुषों के शुक्राणु के उत्पादन को रोकने के लिए एक जेल विकसित किया था, जिसके क्लिनिक ट्रायल में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनका प्रायोगिक उत्पाद एक एक हार्मोनल जेल है, जिसे पुरुषों को रोज एक बार अपने कंधों पर लगाना हैं। समय के साथ, यह वृषण में शुक्राणु के उत्पादन को रोक देगा।

पुरुष गर्भनिरोधक विकसित करने में दशकों की विफलता के बाद, शोधकर्ताओं को अंतत: एक बड़ी सफलता मिली है। शोधकर्ताओं ने पुरुषों के शुक्राणु के उत्पादन को रोकने के लिए एक जेल विकसित किया था, जिसके क्लिनिक ट्रायल में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनका प्रायोगिक उत्पाद एक एक हार्मोनल जेल है, जिसे पुरुषों को रोज एक बार अपने कंधों पर लगाना हैं। समय के साथ, यह वृषण में शुक्राणु के उत्पादन को रोक देगा।

बाल प्रत्यारोपण 7 खोज विज्ञापन

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और गैर-लाभकारी जनसंख्या परिषद द्वारा विकसित किए गए इस जेल में शोधकर्ताओं ने दो हार्मोन नेस्टोरोन (एक प्रोजेस्टिन) और टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल किया है, जो पुरुष सेक्स हार्मोन है। बता दें, नेस्टोरोन वृषण में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को दबाता है और शुक्राणु के विकास को भी रोकता है।

पुरुष गर्भनिरोधक जेल कैसे काम करता है?

कंधे की हड्डियों के बीच 5 मिलीलीटर हार्मोनल जेल को प्रतिदिन एक बार लगाया जाता है। जेल का सेजेस्टेरोन एसीटेट घटक, जो एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, वृषण में टेस्टोस्टेरोन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन को दबाता है, जिससे शुक्राणु उत्पादन बाधित होता है।

क्या पुरुष गर्भनिरोधक सुरक्षित और प्रभावी है?

शोधकर्ता 2005 से इस जेल की खुराक को तैयार करने पर काम कर रहे हैं। उनके हाल के चरण 2बी परीक्षणों में शामिल 300 से अधिक जोड़ों ने इसे सही पाया है। बता दें, प्रति मिलीलीटर वीर्य में लगभग 15 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं, जिनकी संख्या इस जेल को लगाने के बाद प्रति मिलीलीटर 1 मिलियन से कम हो गयी। शुक्राणुओं की ये संख्या गर्भावस्था को रोकने के लिए पर्याप्त कम है। चूंकि गर्भनिरोधक जेल अभी परीक्षणों से गुजर रहा है, इसलिए शोधकर्ता इसके लंबे समय की सुरक्षा और प्रभावकारिता की अभी भी जांच कर रहे हैं है। लेकिन उनके शोध के शुरुआती निष्कर्ष आशाजनक हैं।

पुरुष गर्भनिरोधक कब उपलब्ध हो सकता है?

इस वर्ष के अंत तक जेल का परीक्षण समाप्त होने की उम्मीद है, जिसके बाद शोधकर्ता अगले चरण में परिणामों का विश्लेषण करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक अधिकारी को उम्मीद है कि यह सकारात्मक परिणाम दिखाता रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, और अभी, कोई वाणिज्यिक भागीदार नहीं है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की शाखा प्रमुख डायना ब्लिथ ने कहा, हम परिणामों से वास्तव में उत्साहित हैं। संयोजन हमारी अपेक्षा से बेहतर, तेज़ दमन प्रदान करता है।

शादी के 1 महीने पहले कर लें ये काम, चेहरे पर आएगा निखार

अगर आपकी शादी होने जा रही है और आप भी स्किन केयर रुटीन फॉलो करना चाहते हैं, तो इन टिप्स को जरुर का पालन करें। फ्लॉलेस ब्राइडल स्किन मिलेगी।

जीवन का सबसे खास पल होता है शादी का दिन, इस दिन दुल्हन सबसे खूबसूरत दिखें इसके लिए इन जरुरी टिप्स को फॉलो करना जरुरी है। लेकिन, शादी की शॉपिंग और कई तैयारियों के चलते अक्सर ब्राइड खुद की ब्यूटी का उतना ध्यान नहीं रख पाती हैं, जितना की उन्हें रखना चाहिए। ऐन वक्त पर कई सारे ट्रीटमेंट्स लेने से, जेब के साथ ही स्किन पर भारी पड़ता है।

सीटीएम रुटीन फॉलो करें

शादी की तैयारियों में आप चाहे कितना भी बिजी क्यों न हों, लेकिन अपने सीटीएम रुटीन को रोज फॉलो करना न भूलें। ष्टञ्जरू यानी क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइश्चराइजिंग, इन तीनों स्टेप्स को डेली फॉलो करें। ये आपकी स्किन को किसी भी तरह के बिल्ड-अप से बचाएगी और पिंपल्स-एक्ने के साथ ही डेड स्किन के कारण कम हो सकने वाले ग्लो की स्थिति को भी रोकेगी।

हेल्दी डाइट शुरु कर लें

ब्राइडल स्किन केयर में सिर्फ ऊपरी स्किन का ख्याल रखना ही नहीं बल्कि आप क्या खा रही हैं, ये भी जरुरी है। वहीं, अपनी डाइट में ऐसे फलों और सब्जियों को शामिल करना शुरु करें, जो विटामिन-सी, विटामिन-ए, एंटीऑक्सिडेंट्स, ओमेगा और हेल्दी फैट्स से भरपूर हों। इसके साथ ही हाइड्रेशन के लिए पर्याप्त पानी की मात्रा लेने का भी पूरा ख्याल रखें।

होममेड फेस पैक से पाएं ग्लोइंग स्किन

घर पर बनाएं होममेड फेस पैक, इससे आपकी स्किन ग्लोइंग नजर आएगी। होममेड ब्यूटी हैक्स को इस्तेमाल कर, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा।

दही और हल्दी का फेस पैक

एक कटोरी में दो चम्मच दही, एक चम्मच नींबू का रस और दो चुटकी हल्दी मिलाएं। इस मिक्स को चेहरे पर 15 मिनट रखें और वॉश कर लें। ये स्किन को सॉफ्ट, सपल और वन-टोन बनाने में मदद करेगा।

बेसन और दूध फेस पैक

अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप दो चम्मच बेसन में एक चम्मच गुलाब जल और दो चम्मच दूध मिलाकर लगाएं।

अच्छी नींद भी जरुरी है

ग्लोइंग स्किन के लिए डाइट और स्किन केयर के साथ नींद लेना भी जरुरी है। इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, उतना ही आपकी स्किन ग्लो करेगी और डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। वहीं, आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा।

गुलाब जल के साथ भूल से भी मिक्स ना करें ये चीजें

गुलाब जल को एसेंशियल ऑयल के साथ मिक्स करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं माना जाता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा करने से समस्या ना हो। लेकिन अगर किसी को फ्रेगरेंस से एलर्जी है या फिर अस्थमा की समस्या है तो इससे उन्हें परेशानी हो सकती है।

जब स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात होती है तो उसमें रोज़ वाटर या नी गुलाब जल का नाम अवश्य लिया जाता है। अपनी स्किन को ठंडक पहुंचाने से लेकर उसे टोन व क्लीन करने के लिए भी गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर से, गर्मी के दिनों में गुलाब जल का इस्तेमाल करना स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अमूमन हम इसे स्किन पर ऐसे ही लगाते हैं या फिर किसी अन्य इंग्रीडिएंट के साथ इन्हें मिक्स करके अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं। हालांकि, ऐसे भी कई इंग्रीडिएंट होते हैं, जिनके साथ रोज वाटर को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ इंग्रीडिएंट्स के बारे में बता रहे हैं, जिनके साथ आपको गुलाब जल मिक्स नहीं करना चाहिए-

एसेंशियल ऑयल के साथ ना करें मिक्स

गुलाब जल को एसेंशियल ऑयल के साथ मिक्स करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं माना जाता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा करने से समस्या ना हो। लेकिन अगर किसी को फ्रेगरेंस से एलर्जी है या फिर अस्थमा की समस्या है तो इससे उन्हें परेशानी हो सकती है। इसलिए, बेहतर होगा कि आप एसेंशियल ऑयल के साथ गुलाब जल को मिक्स करने की भूल ना करें।

बेकिंग सोडा

आज के समय में हम बेकिंग सोडा को भी अपने स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा के साथ गुलाब जल को मिक्स करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। दरअसल, बेकिंग सोडा का पीएच स्तर लेवल काफी हाई होता है और जब इसे गुलाब जल के साथ मिक्स किया जाता है तो इससे आपकी स्किन कठोर और रूखी हो जाती है। जिसके कारण आपको स्किन में जलन या इरिटेशन की समस्या हो सकती है।

नींबू का रस

नींबू का रस बहुत अधिक एसिडिक होता है, जिसके कारण इसके इस्तेमाल से स्किन पर जलन की समस्या हो सकती है। इसके साथ जब गुलाब जल को मिक्स किया जाता है, तो इससे स्किन में सेंसेटिविटी से लेकर जलन आदि की समस्या हो सकती है।

करें व्हाइट शर्ट, मिलता है फैशनेबल ट्विस्ट

सीजन गर्मियों का हो या फिर बरसात का, व्हाइट शर्ट का फैशन कभी आउट नहीं होता है। खासतौर पर महिलाओं के बीच सिंपल व्हाइट शर्ट को फैशनेबल ट्विस्ट देने का अलग ही क्रेज है। आपने इसे सर्दियों में ब्लेज़र या ओवरकोट के साथ पहना होगा लेकिन अब आपको इसके साथ समर स्टाइल ट्राई करना चाहिए।

सफेद शर्ट को स्टाइल करने के असंख्य तरीके हैं क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे पतलून से लेकर स्कर्ट तक लगभग किसी भी चीज़ के साथ जोड़ा जाता है। अगर आप सही स्टाइल करते हैं तो आप इसे कैजुअल आउटिंग के लिए भी पहन सकते हैं। स्कर्ट के साथ स्टाइल करें एक स्कर्ट सफेद शर्ट को स्टाइल करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। आप गर्मियों के मौसम में आसानी से स्कर्ट पहन सकती हैं।

यह गलत धारणा है कि आप एक शॉर्ट स्कर्ट को सफेद शर्ट के साथ डाल सकते हैं, लेकिन आप लॉंग स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हैं। सफेद के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे किसी भी दूसरे रंग के साथ जोड़ सकते हैं। यह आपके द्वारा चुने गए हर रंग के साथ अच्छा मैच करता है। आप किसी भी अवसर के अनुसार इसे स्टाइल कर सकते हैं।

आपको वाइट शर्ट और स?कर्ट का लुक बेहद अच्छा लगता है। आप इसके साथ चंकी ज्वैलरी भी जोड़ सकते हैं। एक ड्रेस के रूप में पहनें यदि आप शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं? तो चिंता न करें, इसके लिए आप अपनी सफेद शर्ट को ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी सफेद शर्ट को बहुत आसानी से ड्रेस में बदल सकते हैं। इसके लिए आप बस एक लंबी सफेद शर्ट लें और इसे एक ड्रेस के रूप में पहनें। आप अपनी छाती के नीचे एक चौड़ी बेल्ट लगाएं ताकि यह एक ड्रेस की तरह दिख सके। यदि आप दिन के समय बाहर जा रहे हैं, तो लुक को पूरा करने के लिए आप एक टोपी भी जोड़ सकते हैं। पॉप का रंग देने के लिए, आप उसके साथ एक कोलॉफुल बेल्ट या स्कार्फ भी जोड़ सकते हैं। साथ ही अपने लुक को पूरा करने के लिए अपने बालों में स्कार्फ बांधें।

व्हाइट शर्ट को बनाएं ऑफ शोल्डर

यदि आपके पास एक सफेद शर्ट है, तो आप इसे ऑफ शोल्डर बना सकते हैं। आप अपनी सफेद शर्ट को कई तरीके से ट्राई कर सकते है। आप इसे ऑफ शोल्डर बनाकर एक ट्रेंडी स्टाइल में कैरी करें। जिसे आप इस समर में चुन सकती हैं।

आप अपनी सफेद शर्ट लें और आप इसे ऑफ शोल्डर टॉप बनाएं, जिसमें आप अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोलें। फिर आप इसे आप अपने कंधे से नीचे उतारें, ताकि यह एक ऑफ-शोल्डर टॉप जैसा दिखे।

श्रग के रूप में पहनें

सफेद शर्ट को स्टाइल करने का एक और तरीका है इसे श्रग के रूप में पहनना। आप इसे एक सुंदर गर्मियों की ड्रेस पहन सकते हैं और एक सफेद शर्ट के साथ इसकी तारीफ कर सकते हैं। आप अपनी जींस के साथ एक टी-शर्ट भी पहन सकते हैं और बाद में एक श्रग के रूप में सफेद शर्ट जोड़ सकते हैं।

पलाज़ो के साथ पेयर बनाएं

पलाज़ोस सबसे ट्रेंडी स्टाइल है, जिसे आप इस गर्मी-सर्दी दोनों में पहन सकती हैं। पलाज़ोस भी एक बढ़िया विकल्प है। आप विभिन्न स्टाइल और रंगों में पलाज़ोस पा सकते हैं, जो एक सफेद शर्ट के साथ आसानी से मेल खा सकते हैं। आप व्हाइट शर्ट है के साथ लूज़ पलाज़ो या पलाज़ो पैंट भी चुन सकते हैं, जो एक ही समय में बेहद स्टाइलिश और औपचारिक दिखते हैं।

व्हाइट शर्ट विद नॉट नॉट स्टाइल शर्ट का फैशन नया नहीं है, मगर इसका क्रेज आज भी महिलाओं में देखा जाता है और यह बहुत ट्रेंडी लुक देता है। इस तस्वीर में मलाइका अरोड़ा ने भी नॉट वाली व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स वाला प्लाजो पहना है। आप इसे और भी कई तरह से स्टाइल कर सकती हैं- नॉट वाली व्हाइट शर्ट को आप डेनिम जींस के साथ पहन सकती हैं। आप इस तरह की शर्ट को डेनिम स्कर्ट के साथ भी पहन सकती हैं। नॉट वाली शर्ट को आप ब्लैक या किसी अन्य सॉलिड कलर वाले जंपसूट के साथ भी क्लब कर सकती हैं।

फटी एड़ियों का इस तरह करें इलाज

फिटकरी का इस्तेमाल कई घरेलू कामों में किया जाता है। किचन में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इसके इलावा फिटकरी में औषधीय गुण होते हैं जो शारीरिक परेशानियों से दूर रखने में मदद करते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन को एलर्जी से राहत दिलाते हैं। रूखी और बेजान त्वचा को ठीक करने के अलावा आप फटी एड़ियों पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जानिए फटी एड़ियों से निपटने के लिए कैसे करें फिटकरी का इस्तेमाल-

अपनाएं ये देसी नुस्खा

एड़ियों पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा फटने लगती हैं। कई लोगों में ये समस्या इतनी बढ़ जाती है की खून तक आने लगता है। ऐसे में आप फिटकरी का इस्तेमाल कर इस समस्या से निपट सकते हैं। इसके लिए पानी गर्म करें और एक कटोरी में फिटकरी लें, इसे गर्म पानी के कटोरे के बीच में रख दें। कुछ देर में फिटकरी पूरी पिघल जाएगी। जब ऐसा हो जाए तो इसमें नारियल का तेल मिक्स करें और फिर अपनी एड़ियों पर लगाएं। कुछ ही दिनों में आपकी फटी एड़ियां पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी।

सबसे पहले करें ये काम

इस देसी नुस्खे को अपनाने से पहले आप अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके लिए पैरों को पानी और साबुन से धोएं। फिर गुनगुने पानी में 10 से 12 मिनट के लिए पैरों को डूबों कर रखें। इसके बाद पैरों को बाहर निकालें और फिर प्यूबिक टोन की मदद से साफ करें। इसके बाद इस नुस्खे को अपनाएं।

कई लोगों में ये समस्या इतनी बढ़ जाती है की खून तक आने लगता है। ऐसे में आप फिटकरी का इस्तेमाल कर इस समस्या से निपट सकते हैं।

महिलाओं की तरह पुरुषों के शरीर पर भी होते हैं स्ट्रेच मार्क

स्ट्रेच मार्क को लेकर अक्सर लोग यह सोचते हैं कि यह सिर्फ महिलाओं को ही होता है। क्योंकि डिलीवरी के समय पेट पर खिंचाव पड़ता है। जिसके कारण महिलाओं की जांघ और पेट पर सफेद या लाल रंग की लकीरें उभर आती हैं। हालांकि इन मार्क को दवा और क्रीम के जरिए सही किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि स्ट्रेच मार्क एक सामान्य स्थिति है, जो सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी देखने को मिलती है। एक स्टडी के अनुसार जब डर्मिस बहुत तेजी से खिंचती है, तो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर टूटने लगते हैं। इससे त्वचा पर खिंचाव यानी की स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क के कारण पुरुषों को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे पहले यह समझना काफी जरूरी है कि यह जीवन का इस हिस्सा है। इसलिए इन स्ट्रेच मार्क के होने पर कभी भी कम आत्मसम्मान की भावना नहीं लानी चाहिए। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको पुरुषों में स्ट्रेच मार्क के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं।

स्ट्रेच मार्क क्रीम

एक स्टडी के अनुसार, रेटिनॉइड्स और अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड वाली क्रीम को स्ट्रेच मार्क पर लगाने से इससे छुटकारा मिल जाता है।

लेजर थेरेपी

स्ट्रेच मार्क का इलाज लेजर थेरेपी के जरिए भी किया जाता है। इस प्रक्रिया से कोलेजन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। जिसके कारण स्ट्रेच मार्क के निशान कम होते हैं।

माइक्रोडर्माब्रेशन

माइक्रोडर्माब्रेशन एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है। जिसमें स्किन की ऊपरी परत को हटाया जाता है। इससे त्वचा पर खिंचाव के निशान कम होने के साथ ही आपकी त्वचा एकदम चिकनी हो जाती है।

सर्जिकल प्रक्रिया

स्ट्रेच मार्क्स को त्वचा से हटाने के लिए टमी टक या थाइज लिफ्ट जैसी सर्जिकल प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

राहुल गांधी को मानहानि मामले में कोर्ट से मिली जमानत

बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक अदालत ने मुख्यधारा के समाचार पत्रों में अपमानजनक विज्ञापन जारी करने के लिए भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा दायर एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को जमानत दे दी। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। कांग्रेस ने सभी सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए 40 प्रतिशत कमीशन वसूलने का आरोप लगाते हुए विज्ञापन में पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार रेट कार्ड भी जारी किया। भाजपा एमएलसी और महासचिव केशव प्रसाद ने मानहानि का मामला दायर किया था और दावा किया था कि डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन दिए थे।

कर्नाटक के राज्यपाल ने नागेंद्र का इस्तीफा स्वीकार किया

बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राजभवन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकारी निगम से धन के अवैध हस्तांतरण के आरोपों के बीच नागेंद्र ने बृहस्पतिवार को इस्तीफा दे दिया था। राजभवन की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करने की सिफारिश की थी। राजभवन की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में अवैध हस्तांतरण करके 87 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में इसके कर्मचारी चंद्रशेखर पी ने आत्महत्या कर ली थी। कर्मचारी ने मृत्यु पूर्व लिखे एक नोट में धन हस्तांतरित करने के लिए उच्च स्तर से उन पर दबाव बनाए जाने की बात कही थी।

कांग्रेस को मिला निर्दलीय विशाल पाटिल का समर्थन

नईदिल्ली। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। लेकिन मंगलवार को घोषित लोकसभा परिणामों में एक शतक से पीछे रह गई। कांग्रेस ने अपने खाते में एक और सांसद जोड़ा है। महाराष्ट्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के बागी विशाल पाटिल ने गुरुवार को पार्टी को समर्थन दिया। चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतीं. कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम, जिन्होंने पार्टी के भीतर उनके लिए लड़ाई लड़ी थी। विशाल पाटिल के समर्थन से लोकसभा में कांग्रेस की ताकत 100 तक बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल के पोते, विशाल पाटिल ने भाजपा के संजयकाका पाटिल को हराकर सांगली सीट से लोकसभा चुनाव जीता। एमवीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था में सांगली संसदीय सीट शिवसेना-यूबीटी को सौंपे जाने के बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया था और निर्दलीय चुनाव लड़ा था।

सरकार गठन से पहले उमर अब्दुल्ला का एनडीए पर हमला

कश्मीर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को केंद्र सरकार में अल्पसंख्यकों का लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर निशाना साधा है। उनकी यह प्रतिक्रिया केंद्र में सरकार गठन से ठीक पहले आई है। उमर अब्दुल्ला ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये पोस्ट में लिखा, यह सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, एनडीए मुस्लिम मुक्त, ईसाई मुक्त, बौद्ध मुक्त, सिख मुक्त है और फिर भी सरकार 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करेगी। उमर की प्रतिक्रिया एक रिपोर्ट पर थी, जिसमें बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एनडीए का हिस्सा रहे विभिन्न अन्य दलों से चुने गए सांसद हिंदू थे। मालूम हो कि 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर सात चरणों में संपन्न हुए थे। अंतिम चरण 1 जून को हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 543 सीटों में 240 सीटें जीती हैं।

एनपीपी अरुणाचल में पेमा खांडू सरकार को समर्थन देगी

ईटानगर। नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू सरकार को समर्थन देगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एनपीपी अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थांगवांग वांगहम ने कहा कि पार्टी ने हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में लोगों के जनादेश को स्वीकार कर लिया है। वांगहम ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी, जो कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (एनईडीए) की सहयोगी है, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू सरकार को अपना समर्थन देगी। उन्होंने राज्य में लोगों की आकांक्षाओं को बरकरार रखने के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया और कहा, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। प्रदेश की लोंगडिंग-पुमाओ विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले वांगहम ने कहा कि पार्टी के पास राज्य, क्षेत्र और देश के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण है।

नीट परीक्षा में धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो : खरगे

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (स्नातक) में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि इसकी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को न्याय मिल सके। नीट का परिणाम गत चार जून को घोषित किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गया है। इसकी सीधी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षाओं में भाग लेना, फिर अनेकों अनियमितताओं से जूझना, पेपर लीक के चक्रव्यूह में फँसना- उनके भविष्य से खिलवाड़ है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश के युवाओं को ठगा है। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि उच्चतम न्यायालय की देखरेख में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जिससे नीट व अन्य परीक्षाओं में भाग लेने वाले हमारे प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को न्याय मिले। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके परिणाम में भी भ्रष्टाचार हुआ है। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताओं की बातें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर, परिणाम आने के बाद देश भर में कई बच्चों के आत्महत्या करने की खबरें हैं। यह बहुत दुखद और झकझोरने वाला है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है? प्रियंका गांधी ने कहा, छात्र-छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच कराकर इन वाजिब शिकायतों का निस्तारण करे? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में लाखों परीक्षार्थियों के साथ घोटाला पूरी तरह से अस्वीकार्य और अक्षम्य है।

यह देश के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है, जिसकी उच्चतम न्यायालय की देखरेख में उच्च स्तरीय जांच तुरंत होनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस साल पहले इसमें पेपरलीक होने का समाचार आया, जिसे दबा दिया गया। अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के कई परीक्षार्थियों ने छात्रों के अंक बढ़ाए जाने के आरोप लगाए हैं।

मोदी चुने गए एनडीए के नेता, बैठक से पहले संविधान को माथे से लगाया

राजनाथ ने नाम का किया प्रस्ताव, शाह, गडकरी और नायडू ने किया समर्थन, नीतीश बोले- मिलकर चलेंगे

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल की बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारत के संविधान को अपने माथे से लगाया। एनडीए के सांसदों की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मौजूदगी में गठबंधन के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। राजनाथ ने कहा कि 1962 के बाद यह पहला मौका होगा जब कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। संविधान सदन (पुरानी संसद) में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों, मुख्यमंत्रियों और एनडीए के अन्य नेताओं ने मोदी-मोदी के नारे लगाए।

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव में दोबारा जीत के लिए सभी को बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के नेता, बीजेपी और एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया है। मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं। अमित शाह ने कहा कि ये प्रस्ताव सिर्फ यहां बैठे लोगों की इच्छा नहीं है. ये देश के 140 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है। ये देश की आवाज है कि पीएम मोदी अगले 5 साल तक देश का नेतृत्व करें। बीजेपी सांसद नितिन गडकरी और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सभी को बधाई दे रहे हैं क्योंकि हमने शानदार बहुमत हासिल किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा, 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन-रात प्रचार किया है। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत और अंत किया। आंध्र प्रदेश में हमारी 3 सार्वजनिक बैठकें और 1 बड़ी रैली हुई और

इसने आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर डाला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास एक दूरदर्शिता और एक जोश है, उनका क्रियान्वयन बहुत उत्तम है। वह अपनी सभी नीतियों को सच्ची भावना से क्रियान्वित कर रहे हैं...आज भारत के पास सही नेता हैं- वह हैं नरेंद्र मोदी। यह भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर आप अभी चूक गए तो हम हमेशा चूकेंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री- जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के सभी रुके हुए काम होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब एक साथ आए हैं और हम सब आपके (पीएम मोदी) साथ मिलकर काम करेंगे। आप रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि आप यह शपथ आज ही लें। जब भी आप शपथ लेंगे, हम आपके साथ होंगे... हम सब आपके नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। नीतीश ने कहा कि अगली बार जब आप आएं तो कुछ लोग जो इधर उधर जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। हमको पूरा भरोसा है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को लोकसभा के नेता के रूप में नामित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया।

सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक और देश चलाने के लिए सर्वमत : मोदी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। इसके बाद कार्यवाहक पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि जो साथ विजय होकर आए हैं, वो सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन-रात परिश्रम किया है, उन लोगों ने न दिन देखा, न रात देखी। इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन से उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। साथियों मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुनकर मुझे नया दायित्व दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

पीएम मोदी ने कहा, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और गठबंधन की राजनीति के इतिहास में चुनाव पूर्व गठबंधन इतना कभी मजबूत नहीं हुआ, जितना एनडीए हुआ है। यह गठबंधन की जीत है। हमने बहुमत हासिल किया है। मैं कई बार कह चुका हूं। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है। देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस तरह बहुमत देकर सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, हम सभी का दायित्व है कि सर्वमत का सम्मान कर देश को आगे ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एनडीए को करीब-करीब तीन दशक हो चुके हैं। आजादी के 75 साल में तीन दशक एनडीए का होना सामान्य घटना नहीं है। विविधता के बीच तीन दशक की यह यात्रा बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। आज गर्व के साथ कहता हूं कि एक समय संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मैं इस गठबंधन का हिस्सा था और आज सदन में बैठकर आपके साथ काम करते-करते मेरा भी नाता इससे तीस सालों का हो गया है। मैं कह सकता हूं कि यह सबसे सफल गठबंधन है। पांच साल का कार्यकाल होता है, लेकिन इस गठबंधन ने तीस साल में से पांच-पांच साल के तीन कार्यकाल पूरे किए हैं और गठबंधन चौथे कार्यकाल में प्रवेश कर रहा है।

उन्होंने कहा, व्यक्तिगत जीवन में मुझे जवाबदारी का एहसास करता हूं। 2019 में जब आप सभी ने मुझे नेता के रूप में चुना था, तब मैंने एक बात पर बल दिया था- विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे बीच विश्वास का सेतु बहुत मजबूत है। अटूट रिश्ता विश्वास के मजबूत धरातल पर है। ये पल भावुक करने वाला भी है। आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है।

पीएम मोदी ने कहा, बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, उन्हें शायद सूट नहीं करता होगा। इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए। एनडीए को आज देश के 22 राज्यों में लोगों ने सरकार बनवाकर सेवा का मौका दिया है। हमारा गठबंधन सच्चे अर्थ में भारत की असली आत्मा, भारत की जड़ों में जो रचा-बसा है, उसका प्रतिबिंब है। हमारे देश में 10 ऐसे राज्य हैं, जहां आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है। जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से सात में एनडीए सेवा कर रहा है। हम सर्वधर्म समभाव वाले संविधान को समर्पित हैं। गोवा हो, पूर्वोत्तर हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में ईसाई भाई-बहन रहते हैं, उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में हमें सेवा का अवसर मिला है।

खेल

प्रमुख समाचार

स्कॉटलैंड ने नामीबिया को पांच विकेट हराया

बारबाडोस। आईसीसी टी20 विश्व कप में

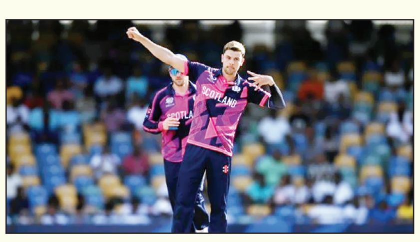

स्कॉटलैंड ने कमाल कर दिया। तीन अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। गत चैंपियन इंग्लैंड और पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पीछे छूट गए। इंग्लैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। दोनों टीम में अंक का बंटवारा हुआ था। 5 विकेट से नामीबिया को हराया। 9 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल किया। नामीबिया को अंत में कुछ लचर गेंदबाज़ी का खामियाजा भुगतना पड़ा और खेल फिसल गया।

नामीबिया ने नौ विकेट पर 155 रन बनाये और स्कॉटलैंड ने नौ गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान रिची बेरिंगटन ने 35 गेंद में नाबाद 47 रन बनाये और पांचवें विकेट के लिये माइकल लीस्क) 17 गेंद में 35 रन) के साथ 74 रन की साझेदारी की। स्कॉटलैंड की चार टी20 मैचों में नामीबिया पर यह पहली जीत है।

स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हुए मैच से एक अंक मिला था। अब वह तीन अंक लेकर शीर्ष पर है। आस्ट्रेलिया और नामीबिया के दो अंक हैं। नामीबिया ने ओमान को पहले मैच में सुपर ओवर में हराया था। ऑस्ट्रेलिया का सामना शनिवार को इंग्लैंड से होगा। कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 30 गेंद में 52 रन बनाए।

पांचवें विकेट के लिये जेन ग्रीन (28) के साथ 51 रन जोड़े। इसकी मदद से नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 155 रन बनाये। इरास्मस ने 14 रन देकर दो विकेट लिये। स्कॉटलैंड का स्कोर एक समय 11 ओवर में चार विकेट पर 73 रन था लेकिन बेरिंगटन और लीस्क ने टीम को जीत तक पहुंचाया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 76,693 तो निफ्टी 23,290 अंक पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव माहौल देखने को मिला और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से बन रही मजबूत सरकार की उम्मीदों से बाजार उठ खड़ा हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज लगभग सपाट खुला। लेकिन एक बार फिर बन रही एनडीए सरकार और वृद्धि दर के आंकड़ों से उत्साहित होकर कारोबार के दौरान 1,720 अंक से ज्यादा उछलकर रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया। अंत में सेंसेक्स 1618.85 अंक या 2.16 प्रतिशत चढ़कर 76,693.36 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2.05 फीसदी या 468.75 अंक की बढ़त लेते हुए 23,290.15 अंक के लेवल पर बंद हुआ। इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान निफ्टी भी 498.8 अंक बढ़कर 23,320.20 अंक के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। सेंसेक्स में शामिल सभी कंपनियों के शेयर आज हरे निशान में बंद हुए।

रीपो रेट 6.50 फीसदी पर कायम : आरबीआई गवर्नर

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। मुद्रास्फीति को लेकर चिंता के बीच रीपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। रीपो रेट अभी भी 6.5 फीसदी पर बरकरार है। एमपीसी के 6 में से 4 सदस्यों ने रेट को स्थिर रखने पर फैसला किया। आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7 फीसदी से बढ़ाकर 7.2 फीसदी किया। उन्होंने कहा कि मार्च-अप्रैल में खुदरा महंगाई में कमी आई है लेकिन फूड इनफ्लेशन में अभी भी तेजी है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.1 फीसदी से बढ़ाकर 7.3 फीसदी किया गया है। वहीं, जुलाई-सितंबर के लिए 7.2 प्रतिशत, अक्टूबर-दिसंबर के लिए 7.3 प्रतिशत और जनवरी-मार्च के लिए 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

आरबीआई ने थोक जमा की सीमा बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये की

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को थोक सावधि जमा की सीमा मौजूदा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये करने की घोषणा की। थोक सावधि जमा पर खुदरा सावधि जमा की तुलना में थोड़ा अधिक ब्याज मिलता है, क्योंकि बैंक अपनी नकदी प्रबंधन प्रक्रिया के तहत अलग-अलग दरें प्रदान करते हैं। अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के पास दो करोड़ रुपये तक की एकल रुपया सावधि जमा, खुदरा सावधि जमा का हिस्सा होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक नीति की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि थोक जमा सीमा की समीक्षा के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफबी के लिए ''तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा'' के रूप में थोक जमा की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.2% बढ़ाया

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीाआई) ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को सात प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। निजी उपभोग में सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्र की मांग मजबूत होने से केंद्रीय बैंक ने वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने शुक्रवार को यहां द्विमासिक मौद्रिक नीति पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। उन्होंने कहा, ''2024-25 में अभी तक घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत हैं। घरेलू मांग बढ़ने से विनिर्माण गतिविधियों में तेजी आई है।'' दास ने कहा कि विभिन्न आर्थिक संकेतकों से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र की रफ्तार भी कायम है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति की पिच का आकलन कितना जरूरी

(गतांक से आगे...)

तमाल बंद्योपाध्याय

मई में अमेरिका के केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व ने लगातार छठी बार फेडरल फंड दर के 5.25-5.5 प्रतिशत के स्तर में कोई बदलाव नहीं किया है जो 23 साल का उच्चतम स्तर है। क्या यह अगली बैठक में दरों में कटौती करेगा? इसकी संभावना नहीं है। दरअसल स्थिर मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई फिलहाल जारी रहेगी।

मई में, बैंक ऑफ इंगलैंड (बीओई) ने भी लगातार छठी बार अपनी दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। बीओई के गवर्नर का मानना है कि 'चीजें सही दिशा में बढ़ रही हैं इसलिए वे आशावादी हैं' लेकिन आधार दर में कटौती करने से पहले उन्हें मुद्रास्फीति में गिरावट के 'अधिक प्रमाण' देखने की जरूरत है।

दरों में कटौती तो जरूर होगी लेकिन साल की शुरुआत में बाजार जितनी दर कटौती पर दांव लगा रहे थे अब उतनी नहीं लगा पा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर एक साल तक के ब्याज दरों का रुझान भारत में रातों-रात होने वाले इंडेक्स स्वैप के बराबर है। पहले जितनी उम्मीद थी अब ब्याज दरों में उतनी कटौती की संभावना नहीं है।

एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम विनिर्माण से जुड़े कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि है। तेल सहित अन्य जिंसों की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे पहले थोक मूल्य सूचकांक और फिर सीपीआई मुद्रास्फीति प्रभावित होगी। अप्रैल 2024 में सीपीआई मुद्रास्फीति, मार्च के 4.9 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 4.8 प्रतिशत हो गई। गैर-खाद्य, गैर-तेल बुनियादी मुद्रास्फीति पिछले 11 महीनों में लगातार घटकर अप्रैल में 3.2 प्रतिशत हो गई जो मार्च में 3.3 प्रतिशत थी और यह मौजूदा

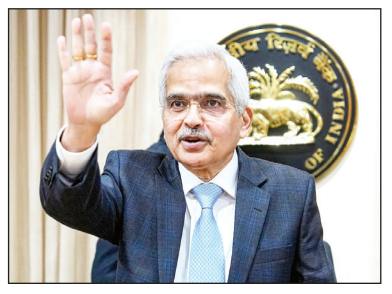

सीपीआई (2012=100) श्रृंखला में सबसे कम है, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में 7.9 प्रतिशत हो गई जो मार्च में 7.7 प्रतिशत थी।

मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सीपीआई मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे जा सकती है लेकिन फिर इसमें तेजी आएगी और यह 5 प्रतिशत को पार कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुद्रास्फीति का जिन्न अब भी बोतल में नहीं बंद है और दास ब्याज दर में कटौती पर विचार करने से पहले इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। खाद्य कीमतों को लेकर जोखिम की स्थिति बनी हुई है और यह काफी हद तक मॉनसून की दिशा पर निर्भर करेगा।

अप्रैल में नीतिगत बयान में कहा गया था कि मजबूत वृद्धि नीति, मूल्य स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नीतिगत गुंजाइश दे रही है। यह रफ्तार जारी है। मार्च तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत बढ़ी जिससे वार्षिक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत हो गई। जनवरी-मार्च अवधि में वृद्धि दिसंबर तिमाही में 8.6 प्रतिशत के विस्तार से कम है लेकिन बाजार की उम्मीद से कहीं अधिक है।

जून की मौद्रिक नीति हर तरीके से यथास्थिति वाली नीति होगी। इसका अर्थ यह है कि दर या रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई अगस्त में अपने रुख (तटस्थता के लिए) में बदलाव कर सकता है जब मौजूदा एमपीसी अपनी आखिरी बैठक करेगी।

हम दर में कटौती कब देखेंगे? ऐसी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। कुछ वक्त तक के लिए आरबीआई मॉनसून की स्थिति और वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट पर नजर रखेगा। अगर वृद्धि में कोई कमी होगी तब ही हमें जल्द ही दरों में कटौती देखने को मिलेगी लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। एक अन्य प्रेरणादायक कारक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दर में कटौती हो सकती है।

भारत में दर में कटौती अक्टूबर से पहले नहीं होगी और यह तभी होगा जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व सितंबर में दर में कटौती करता है। लेकिन, अभी जैसी स्थिति है उसमें इस बात को लेकर किसी को हैरानी नहीं होगी अगर आरबीआई दर कटौती को दिसंबर या फरवरी 2025 तक के लिए टाल दे।

ग्राम बाहपानी सड़क दुर्घटना तथा पिरदा में बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों एवं घायलों को स्वेच्छानुदान से मंजूर की गई राशि

मुख्यमंत्री साय ने नियमों को शिथिल करते हुए स्वेच्छानुदान से डेढ़ करोड़ रूपए से ज्यादा की सहायता राशि मंजूर की

28 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख तथा 23 घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि

रायपुर। राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कबीरधाम जिले के विकासखंड पंडरिया के ग्राम बाहपानी में 20 मई को हुई दु:खद सड़क दुर्घटना एवं बेमेतरा जिले की भिंभौरी तहसील के ग्राम पिरदा में 25 मई को स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में मृतकों के परिजनों तथा घायलों सहित 51 अनुदानग्रहिताओं को अपने स्वेच्छानुदान मद से कुल 01 करोड़ 51 लाख 50 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपए तथा घायलों को 50-50 हजार रूपए के मान से सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

कबीरधाम जिले के ग्राम बाहपानी की सड़क दुर्घटना में 19 मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपए के मान से 95 लाख रूपए तथा इस घटना में 16 घायलों को 50-50 हजार रूपए के मान से कुल 8 लाख रूपए की राशि मुख्यमंत्री साय द्वारा स्वेच्छानुदान मद से मंजूर की गई है। इसी प्रकार बेमेतरा जिले के ग्राम पिरदा की स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में 25 मई को हुए ब्लास्ट में एक मृतक एवं 8 लापता व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रूपए के मान से कुल 45 लाख रूपए की आर्थिक सहायता तथा इसी घटना में 7 घायलों को 50 हजार रूपए के मान से कुल 3 लाख 50 हजार रूपए की सहायता राशि की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है। मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले के ग्राम बाहपानी की सड़क दुर्घटना में मृतक श्रीमती प्यारी बाई, कुमारी सोनम बाई धुर्वे, श्रीमती धनैया बाई धुर्वे, सिरदारी राम धुर्वे, कुमारी किरण, श्रीमती शांति बाई, श्रीमती तिको बाई, श्रीमती मीला बाई, श्रीमती जनिया बाई, श्रीमती मुंगिया बाई, श्रीमती झंगलो बाई धुर्वे, श्रीमती सियाबाई, श्रीमती पैंटोरिन बाई मेरावी, श्रीमती बिस्मत बाई मेरवी, श्रीमती लीला बाई, श्रीमती परसदिया देवी, श्रीमती भारती बाई, श्रीमती कुनती बाई, श्रीमती धानबाई धुर्वे के परिजन को 5-5 लाख रूपए की राशि तथा 16 घायलों श्रीमती ममता, श्रीमती मुन्नी बाई, गुलाब सिंह, दयाराम, शिवनाथ, महावीर, कार्तिक, श्रीमती धन्नू, श्रीमती इन्द्राणी, जोधीराम, अनिल, फूलचंद, श्री मानसिंह, श्रीराम, रम्हउ, बजरू को 50-50 हजार रूपए की सहायता राशि मंजूर की है।

इसी तरह ग्राम पिरदा की स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट में मृतक सेवक राम और 8 लापता व्यक्तियों पुष्पराज देवदास, विजय देवदास, राजू ध्रुव, नीरज ध्रुव, लोकनाथ यादव, शंकर यादव, नरहर यादव, भीष्म साहू के परिजन को 5-5 लाख रूपए की राशि तथा 7 घायलों इन्द्रकुमार रघुवंशी, दिलीप ध्रुव, नीरज यादव, चंदन कुमार, मनोहर यादव, रवि कुर्रे, शेषनाथ निषाद को 50-50 हजार रूपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री साय द्वारा मंजूर की गई है।

विष्णु के सुशासन में रिपोर्ट नहीं, रिजल्ट चाहिएः जायसवाल

स्वास्थ्य मंत्री ने मैराथन बैठक लेकर की समीक्षा, आचार संहिता खत्म होते ही छत्तीसगढ़ में सरकार का काम शुरू

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक लेकर विभाग के कामकाज की समीक्षा की। श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है और सभी मेडिकल कालेज तथा जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। श्री जायसवाल ने अधिकारियों को कहा है कि विष्णु के सुशासन में उन्हें रिपोर्ट नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए ताकि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर मिलती रहें।

श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य मे स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए ये आवश्यक नहीं है कि बजट की उपलब्धता रहे, बल्कि आवश्यक ये है कि मजबूत इच्छाशक्ति हो, हमें ऐसा काम करना है जिससे लोगों के मन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सकारात्मक भाव आए।

मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता- स्वास्थ्य मंत्री ने मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के बारे में बात करते हुए कहा है कि इसको लेकर समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसके लिए जिन क्षेत्रों में इन बीमारियों का संक्रेंद्रण ज्यादा है वहां ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर लोगों को इनसे बचने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने समीक्षा बैठक में विभागीय बजट का आंकलन करते हुए उसे अनुपूरक बजट में शामिल करने के प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके साथ ही नियमित बजट में पारित कार्यो की भी समीक्षा की।

श्री जायसवास ने विभागीय समीक्षा बैठक में चिकित्सकों एवं निचले स्टाफ की पदस्थापना को लेकर चर्चा की और रिक्त पदों को जल्द से जल्द व्यापम एवं पीएससी के माध्यम से भरे जाने के निर्देश दिए।

सुपेबेड़ा में डायलिसिस सेंटर, राज्य में माडल नेफ्रोलाजी सेंटर खोलने की अनुशंसा- स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी को ध्यान मे रखते हुए वहां एक अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर खोलने की अनुशंसा की है। सुपेबेड़ा में बीमार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने और बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में उत्कृष्ट डायलिसिस सेंटर खोलने की अनुशसा की है ताकि वहां के मरीजों को त्वरित लाभ मिल सके। इसके साथ ही श्री जायसवाल ने राज्य भर के किडनी के मरीजो के बेहतर इलाज के लिए राज्य में एक माडल नेफ्रोलाजी सेंटर खोलने की भी अनुशंसा की है।

एनीमिया की दवाइयों के सैंपल की करें रैंडम जांचः श्री जायसवाल- राज्य के अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता की चर्चा करते हुए श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही श्री जायसवाल ने विभाग को निर्देशित किया है कि एनीमिया की बीमारी को ठीक करने के लिए उपलब्ध दवाइयों के सैंपल की अलग-अलग लेबोरेट्री में रैंडम जांच की जाए ताकि इस जरूरी दवा की गुणवत्ता को जांचा परखा जा सके।

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार, एनएचएम के एमडी जगदीश सोनकर, आयुक्त सह संचालक ऋतुराज रघुवंशी, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि विभाग कुलदीप शर्मा, संचालक आयुष सुश्री इफ्फत आरा, सीजीएमएससी एमडी सुश्री पद्मिनी भोई साहू समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भाजपा विधायक दल की बैठक संपन्न

प्रदेश में विशेष रणनीति बनाकर काम करने की योजना बनाई गई-केदार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की एक अहम बैठक शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में रखी गई। बैठक भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

विधायक दल की बैठक के बाद वन मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव के संबंध में जानकारी ली गई। सभी क्षेत्रों में विशेष रणनीति बनाकर काम करने की योजना बनाई गई। प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में भाजपा ने विजय प्राप्त की है। पिछली बार की तुलना में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकसभा में बढ़त बनाई है। इस बार भाजपा ने 10 लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल की है और इस जीत की निरंतरता को बनाए रखने के लिए लगातार कार्य करने की आवश्यकता को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में सभी विधायक जाएंगे, यह ऐतिहासिक पल होगा। श्री कश्यप ने कहा कि भूपेश बघेल किसको नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और किसको नेता के रूप में चुन रहे हैं, यह सभी जानते हैं और उसी के चलते ही भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मात मिली है। भूपेश बघेल अब चाहे कोई भी चुनाव लड़ें उनकी हार सुनिश्चित है और उनको बचाने के लिए कोई राहुल बाबा नहीं आने वाले। विधायक सुशांत शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि संगठनात्मक तौर पर आज भाजपा विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा विधायक दल की बैठक में मंत्री रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, लखन लाल देवांगन, दयाल दास बघेल, श्याम बिहारी जायसवाल सहित भाजपा सभी विधायक, विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे।

अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन @/2047" डॉक्यूमेंट तैयार करने वर्किंग ग्रुप के अधिकारियों की बैठक

लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर दिया जोर

रायपुर। "अमृतकाल- छत्तीसगढ़ विजन@2047" डॉक्यूमेंट तैयार करने वाणिज्य, उद्योग और अधोसंरचना विकास विषय पर गठित वर्किंग समिति की बैठक राज्य नीति आयोग अटल नगर नवा रायपुर के सभा कक्ष में आज आयोजित की गई। वाणिज्य उद्योग और अधोसंरचना विकास से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्किंग समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए। छत्तीसगढ़ में कुशल निवेश और कुशल निवेश तंत्र अपनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता, खाद्य परीक्षण, एवं प्रमाणन सुविधाएं बढ़ाने, औद्योगिक पार्कों की वृद्धि करने, पर्याप्त कुशल कार्यबल की उपलब्धता, लॉजिस्टिक संबंधी बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने, पर्याप्त परिवहन संपर्क स्थापित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के भीतर पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूक और प्रचार-प्रसार करने में ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य श्री के. सुब्रमण्यम ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु, मध्यम एवं दीर्घकालीन विजन एवं रणनीतियों के निर्धारण हेतु अपना सुझाव दिए। के सुब्रमण्यम ने जीडीपी, रोजगार, कृषि एवं संबंधित उद्योग, प्रति व्यक्ति आय, सेवाएं, व्यय एवं निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक, प्रशिक्षित कार्मिक, शासन और नीतियों की अनुकूलता, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए कौशल सुधार जैसे विषयों पर अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिए उच्च उत्पादन वाले क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना महत्वपूर्ण है। सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव ने कहा की सतत एवं पुनर्योजी विकास में ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को कृषि एव प्रसंस्कृत सुपर फूड के पावर हाउस में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य हर्बल उपचार का केंद्र बन सकता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

लेखा प्रशिक्षण परीक्षा नवम्बर-2023 से फरवरी-2024 का परीक्षाफल जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय सेवकों के लिए लेखा प्रशिक्षण परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष 03 सत्रों (मार्च-जून, जुलाई-अक्टूबर, नवम्बर-फरवरी) में संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाता है। इस प्रशिक्षण में राज्य शासन के आधीन कार्यरत सहायक ग्रेड वर्ग-3, अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली वे प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा नामांकित किए जाते है। लेखा प्रशिक्षण परीक्षा में प्रथम प्रयास में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को एक अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय किया जाता है। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा प्रशिक्षण सत्र नवम्बर-2023 से फरवरी-2024 का परीक्षा परिणाम 06 जून 2024 को घोषित किया गया है। संचालक कोष लेखा एवं पेंशन श्री महादेव कावरे ने बताया कि उक्त सत्र में कुल 246 परीक्षार्थियों में से 159 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत 64.63 प्रतिशत रहा। 81 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए है।

इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश

रायपुर। माना विमानतल में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब एक व्यक्ति ने इंडिगो फ्लाइट का आपातकालीन दरवाजा खोलने की कोशिश की. मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में एक व्यक्ति ने इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश की. क्रू मेंबर्स ने 44 वर्षीय व्यक्ति को रोका और प्लेन से उतारा दिया. एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार माना विमानतल पर टेक आफ के पहले विमान के भीतर एयर होस्टेस यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सुरक्षा का डेमो दे रही थीं. उस दौरान एक यात्री ने प्लेन का इमरजेंसी गेट खोलने का कोशिश की. यात्री को इमरजेंसी डोर खोलते देख क्रू मेंबर्स में अफरा-तफरी मच गई. क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर को पकड़ा और पैसेंजर को फ्लाइट से उतार दिया. बताया जा रहा है कि राजिम निवासी यह यात्री सपरिवार दिल्ली जा रहा था. उसकी सीट इमरजेंसी गेट के पास अलाट थी. माना थाना पुलिस इस संबंध में यात्री से पूछताछ में जुटी है. फ्लाइट के क्रू मेंबर्स की सावधानी के कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया.

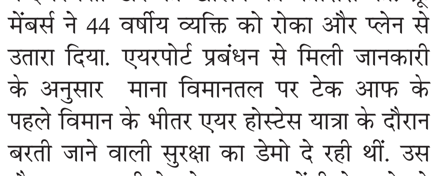

आचार संहिता के दौरान अवैध शराब के मामलों में 597 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। आबकारी विभाग रायपुर द्वारा आचार संहिता के दौरान अवैध मदिरा परिवहन/विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित् विधिवत् प्रभावी कार्यवाही करते हुये कुल 597 प्रकरण कायम कर 15 लाख रूपये से अधिक मूल्य की 2570 लीटर देशी/विदेशी/महुआ शराब एवं लगभग 11 लाख रूपये मूल्य की 16 दोपहिया वाहन एवं 01 कार जप्त किया गया है। मुखबीर सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने चिन्हांकित स्थलों पर छापामार कार्यवाही कर उपरोक्त कार्यवाही की। इसके अलावा यूटर्न कैफे, सांगरिया, सुकुन, नया रायपुर स्थित अरण्यम कैफे, व्ही.आई.पी. रोड़ स्थित पिंड बलूची कैफे, वेलकम ढाबा समोदा, महाराजा ढाबा कोलर, शुभम ढाबा, दबंग ढाबा आरंग में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल दाखिल किया गया। कैफे/ढाबा संचालकों को बिना लायसेंस ग्राहकों को मदिरा नही परोसने की चेतावनी भी दी गई। आबकारी आयुक्त श्री विकास गोस्वामी ने कहा कि जिले में शराब एवं मादक पदार्थो के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने हेतु एवं मदिरा दुकानों से संबंधित शिकायते टेलीफोन नंबर 0771-2428201 एवं टोल फ्री नंबर 14405 जारी किया गया है जिसमें कोई भी आम नागरिक शिकायत कर सकते है जिस पर त्वरित् कार्यवाही की जायेगी।

जैतखम्भ को नुकसान पहुंचाने पर सतनामी समाज में आक्रोश

रायपुर। सतनामी समाज ने बड़ी संख्या में आज राजधानी के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जैतखम्भ को नुकसान पहुंचाने के मामले में ज्ञापन सौंपा. सतनामी समाज ने कलेक्टर से मिलकर उचित कार्रवाई ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है.वहीं आक्रोशित सतनामी समाज ने आज दोपहर महासमुंद कलेक्ट्रोरेट का भी घेराव किया. सतनामी समाज ने गिरौधपुरी जैतखम्भ को क्षतिग्रस्त करने , सोशल मीडिया मे गुरु घासी दास के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और पुलिस के उचित कार्रवाई ना करने के मामलों को लेकर पटवारी कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया. दरअसल, हाल ही में गिरौधपुरी धाम में जैतखम्भ को काटने का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को भी गिरफ़्तार किया है. लेकिन सतनामी समाज के लोगों ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया है, कि पुलिस प्रशासन ने आनन-फानन में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका सतनामी संस्कृति से कोई वास्ता नहीं है. बता दें, इस घटना मामले को लेकर सतनामी समाज रायपुर कलेक्टर सहित सभी जिलों में ज्ञापन सौंप रही है. इसके साथ ही सतनामी समाज ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर

स्कूली बसों की जांची गई फिटनेस, 86 बसें अनफिट

रायपुर। आगामी दिनों में जल्द स्कूलों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बच्चों का स्कूलों में बसों के माध्यम से आना-जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे में स्कूली बसों का फिटनेस दूरूस्त रहें जिससे दुर्घटना से बचाव हो, इसके लिए परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त के निर्देश पर और वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री आशीष देवांगन के मार्गदर्शन में पुराना बस स्टैण्ड पंडरी में जांच शिविर लगाई गई। यह शिविर 18 मई, 25 मई, 29 मई और 01 जून को लगाई गई। शिविर में 516 बसें जांच के लिए आई जिसमें 86 बसों में खामियां पाई गई। जिसके लिए संबंधित संस्था प्रबंधकों को जल्द कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। श्री देवांगन ने बताया कि इन स्कूली बसों में सभी वाहनों के दस्तावेजों, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल बसों के लिए दिये गये दिशा-निर्देशों के पालन तथा मैकनिकल जांच किया गया। साथ ही जिला अस्पताल रायपुर के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा वाहन जांच शिविर में चालक एवं परिचालकों का नि:शुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिसमें रक्तचाप, मधुमेह, दृष्टि क्षमता, मोतियाबिंद आदि की भी जांच की गई। उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह वाले चालकों को लगातार मेडिसीन का उपयोग करने की सलाह दी गई। शिविर में बसों की बारिकी से जांच की गई। यह देखा गया कि हैण्ड ब्रेक सही ढंग से लग रही है या नहीं.

महिलाओं के खाते में आ रही खुशियां,

महतारी वंदन से महिला सशक्तिकरण की राह मजबूत

रायपुर। प्रदेश में विष्णु देव साय सरकार 70 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रुपए अंतरित कर रही है। इस योजना से न केवल महिलाओं को खर्च करने के लिए अपनी स्वयं की राशि मिली है अपितु परिवार भी आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हुए हैं। पूरे प्रदेश में महतारी वंदन योजना आने के बाद महिलाओं द्वारा इस राशि के उपयोग पर नजर डालें तो पाएंगे कि महिलाएं हमेशा की तरह इसमें से कुछ हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित रख रही हैं।

डाकघरों में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर आरडी शुरू किये हैं और प्रदेश के हर डाकघर में महिलाओं की लंबी लाइनें नजर आती हैं। महिलाएं न केवल भविष्य की जरूरतों के अनुरूप इसे बचा रही हैं अपितु परोक्ष रूप से राष्ट्र के सकल घरेलू बचत में भी अपना योगदान दे रही हैं। सकल घरेलू बचत का प्रतिशत जितना मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रवाह के दृष्टिकोण से भी यह अच्छा होगा। रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में म्यूच्युअल फंड के माध्यम से एसआईपी का ट्रेंड भी है। महिलाएं शेयर बाजार का लाभ उठाना चाहती हैं और इसके लिए म्यूच्युअल फंड के माध्यम से इसमें प्रवेश कर रही हैं। अभी तक का ट्रेंड रहा है कि दीर्घावधि के लिए एसआईपी रिटर्न के मामले में काफी उपयोगी रहा है।

दूसरा ट्रेंड शिक्षा में निवेश को लेकर है, जिन महिलाओं के बच्चे प्री ग्रेज्युएट एवं ग्रेज्युएट स्तर पर दी जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वे महतारी वंदन योजना के माध्यम से अर्जित की गई राशि का निवेश कर रही हैं। इसके माध्यम से वे कोचिंग आदि का मासिक खर्च उठा रही हैं और किताबों आदि की व्यवस्था अपने बच्चों के लिए कर रही हैं।

महतारी वंदन योजना की राशि को खर्च करने का एक तीसरा तरीका भी महिलाओं ने निकाला है। वे उद्यमशीलता के रास्ते पर बढ़ी हैं। उद्यमशीलता के लिए जरूरी सिलाई मशीन जैसे उपकरण ईएमआई में खरीद रही हैं और हर महीने राशि का भुगतान महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि से कर रही हैं। महिलाएं बताती हैं कि बीते एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली को देखा है। वे जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं से वायदा किया था कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत एक हजार रुपए की राशि हर महीने महिलाओं के खाते में अंतरित कराएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ की कमान सम्हालते ही बहुत जल्दी यह योजना लागू कर दी और महिलाओं ने कहा कि हमारे खाते में हर महीने यह राशि आ रही है। साय सरकार हर महीने प्रदेश की माताओं-बहनों के खाते में एक हजार रुपए के रूप

ग्राम डूमरखी थाना बलरामपुर में 2 व्यक्तियों की मृत्यु की एसआईटी जांच कराएगी छग सरकारः शर्मा

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार ग्राम डूमरखी थाना बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में दिनांक 26-27 मई 2024 रात्रि को श्री सुजीत स्वर्णकार एवं किरण काशी की रहस्यमय मृत्यु की जांच पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज के पर्यवेक्षण में विशेष जाँच दल (एस.आई.टी.) का गठन किया गया है। बलरामपुर विधायक और मंत्री रामविचार नेताम ने उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एसआईटी गठन करने का आग्रह किया था। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार विशेष जांच दल का गठन किया गया है। 9 सदस्यीय जांच दल में सुश्री रत्ना सिंह, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, रायपुर, मनक राम कश्यप, उप पुलिस अधीक्षक (नक्स.ऑप.) जिला सरगुजा,श्री पी0एस0 भगत, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन) क्षेत्रीय न्याया. विज्ञान प्रयोगशाला, सरगुजा, एस0के0 सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बायोलॉजी) क्षेत्रीय न्याया, विज्ञान प्रयोगशाला, सरगुजा, सुश्री दुर्गेश्वरी चौबे, निरीक्षक, जिला सरगुजा, सुश्री दिव्या शर्मा, उप निरीक्षक, जिला रायपुर, श्री विशाल मिश्रा, प्रधान आरक्षक क्रमांक 168, जिला सूरजपुर, श्री प्रेम सागर साहू, आरक्षक कमांक 511, जिला सूरजपुर, रमन मंडल, आरक्षक कमांक 64, जिला सरगुजा शामिल रहेंगे और जांच समिति घटना स्थल का भ्रमण कर जांच-पड़ताल कर 07 दिवस के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.